रजिस्टर्ड नं० HP/12/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 50 | शिमला, शनिवार, 8 जून, 2002/18 ज्येष्ठ, 1924 | संख्या: 10

विषय सूची

भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	406—425
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	425—427
भाग-3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	427—441
भाग-4	स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	—
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	441—454
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाए तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

8 जून, 2002/18 ज्येष्ठ, 1924 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हुईं :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
No. Fin.-2-C(12)-6/99, dated 29th May, 2002.	Finance Department	Publication of Notification regarding Issue of 10.50% Govenment of Himachal Pradesh (National Small Saving Fund) Non-Transferable Special Securities, 2002.
संख्या 1-29/92-वि0स0, दिनांक 21 मई, 2002.	हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय	हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण नियम, 2002 का प्रकाशन ।
संख्या वि0स0(एफ0 एण्ड एस0) (3-147/98), दिनाक . . . 2002.	-यथोपरि-	हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के (रेल/वायु मार्ग/सड़क मार्ग द्वारा पुक्त पारगमन) नियम, 2002 का प्रकाशन ।

भाग-I विधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATIONS

Shimla-1, the 22nd/23rd May, 2002

No. HHC/GAZ/14-138/82-1-10144.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant *ex post facto* sanction of 20 days commuted leave *w. e. f.* 21-3-2002 to 9-4-2002 and 1 day's earned leave *i.e.* for 10-4-2002 in favour of Shri R. L. Azad, Senior Sub Judge-*cum*-CJM, Kangra at Dharamshala.

Certified that Shri Azad has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Azad would have continued to hold the post of Sub Judge-*cum*-CJM, Kangra at Dharamshala, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 22nd/23rd May, 2002

No HHC/GAZ/14-138/82-1-10153 - Hon'ble the Chief Justice is pleased to order the cancellation of unavailed 3 days earned leave *w.e.f.* 21-3-2002 to 23-3-2002 in favour of Shri R. L. Azad, Senior Sub Judge-*cum*-CJM Kangra at Dharamshala, sanction *vide* this Registry notification No. HHC/GAZ/14-138/82-1-2032-91, dated 18-1-2002

Shimla-1, the 23rd May, 2002

No. HHC/GAZ/14-190/88-10214.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant *ex post facto* sanction of 73 days half pay leave with effect from 27-2-2002 to 31-3-2002 and 6 days earned leave with effect from 1-4-2002 to 6-4-2002 with permission to suffix Sunday falling on 7-4-2002 in favour of Shri K. P. Singh, Additional Chief Judicial Magistrate-*cum*-SJIC, Jawali.

Certified that Shri K. P. Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri K. P. Singh would have continued to hold the post of Additional Chief Judicial Magistrate-*cum* SJIC, Jawali but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 23rd May, 2002

No. HHC/GAZ/14-179/87-I-10194.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant earned leave *w. e. f.* 3-6-2002 to 22-6-2002 with permission to prefix and suffix Sunday falling on 2nd and 23rd June, 2002 in favour of Shri A. K. Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate cum-SJIC, Sarkaghat.

Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Additional Chief Judicial Magistrate-*cum*-SJIC, Sarkaghat but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-1, the 23rd May, 2002

No HHC/Admn. 6 (23)/74-XII-10205.—The Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under rule 1.26 of H. P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the sub Judge-*cum*-JMIC(I), Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the court of Additional Chief Judicial Magistrate-*cum*-SJIC, Sarkaghat and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and IV establishment attached to the Court under head "2014—Administration of Justice" during the leave period of Shri A. K. Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate-*cum*-SJIC, Sarkaghat with effect from 3-6-2002 to 22-6-2002 with permission to prefix and suffix Sandays falling on 2nd and 23rd June, 2002, or until he returns from leave.

Shimla-1, the 23rd/24th May, 2002

No. HHC/Admn. 16 (22)75-II-10283. Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him u/s 139(*b*) of the Code of Civil Procedure, 1908 u/s 297 (*b*) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 4(iv) of the H. P. Oath Commissioners (Appointment and Control) Rules, 1996 is pleased to appoint the following Advocates as Oath Commissioners for a period of two years with effect from the date (s) and at the place(s) shown against their names, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules :-

Sl. No.	Name of Advocate	Date of appointment	Place
1.	Shri Ram Swarup Pundir.	With immediate effect.	Rajgarh, District Sirmaur.
2.	Shri Durga Ram Sharma	25-5-2002	Sangrah, District Sirmaur.

Shimla-1, the 24th May, 2002

No. HHC/Admn. 6 (20)/77-XIV-10273.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice L. S. Panta as Vacation Judge during the Summer Vacation in this High Court with effect from 10-6-2002 to 15-6-2002 (both days inclusive).

By order,

Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th April, 2002

No. 1-37/72-DP-Apptt. (PWD).—The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the transfer of Shri Harbans Kumar, Chief Engineer, Central Zone, H.P. Public Works Department, Mandi and to post him as Chief Engineer, National Highways, HPPWD, Shimla, with immediate effect in public interest. He shall work, as such, under the direct control and supervision of the Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh.

By order,

HARSH GUPTA,
Chief Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171 002, 16 मई, 2002

संख्या सिंचाई 11-43/2002-बिलासपुर.—अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः, गांव काह,

तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना गाहर पधयाण स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : बिलासपुर तहसील : घुमारवीं

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
बाह	106	1	13
	107	6	1
किता ..	2	7	14

शिमला-2, 16 मई, 2002

संख्या सिंचाई 11-30/2002-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव शेरकण्डी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : फतेहपुर

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
शेरकण्डी	97/4/1	0	02	52
	98/2	0	00	70
किता ..	2	0	03	22

शिमला-2, 16 मई, 2002

संख्या सिंचाई 11-34/2002-कांगड़ा.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव राजगीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : इन्दौरा

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
1	2	3		
राजगीर	599/1	0	35	66
	600/1	0	54	40
	610/1	0	04	50
	613/2	0	13	00
किता ..	4	1	07	56

शिमला-2, 16 मई, 2002

संख्या सिंचाई 11-34/2002-कांगड़ा.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मलकवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में जल भण्डार मलकवाल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : नूरपुर

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयरों में
मलकवाल	23	0 00 70

यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत * भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है, या हो सकते है, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव साई, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में पम्प हाउस के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-39/2002-मण्डी ।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

विस्तृत विवरणी

जिला मण्डी तहसील : सुन्दरनगर ।

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा
1	2	3
साई/3	183/1	0 14 19
	172/1	0 05 15
	193/1	0 08 04
	184 सा०	0 12 12
		0 06 00
		0 06 12
	181/1	0 19 11
	180/1	0 01 13
	185/1	0 00 11
	192/1	0 00 08
	569/1	0 04 13
	570/1	0 03 11
	581/1	0 02 16
	किला .. 11	3 14 13

*गांव धारठी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में पेयजल योजना धपाही जल भण्डार के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-40/2002-मण्डी।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

धारठी/33	91/1	0 01 13
	92/1	0 02 11
	93/1	0 00 15
	किला .. 3	0 04 19

*गांव सलवाणा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में पेयजल योजना गड्डीधार जल भण्डार के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-41/2002-मण्डी।

शिमला 2, 16 मई, 2002.

1	2	3
सलवाणा	1150/1	0 02 09

*गांव लैहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में पम्प हाउस के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-35/2002-मण्डी ।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

लैहड/69	337/1	0 01 05

*गांव सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में वाटर टैंक के निर्माण हेतु ।

संख्या सिंचाई 11-36/2002-मण्डी ।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

सलापड़/78	493/1	0 01 05

*गांव कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में नलकूप उठाऊ पेयजल योजना कलौहड के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-37/2002-मण्डी ।

शिमला-2, 16 मई, 2002

कलौहड/27	996/1	1 15 0

*गांव जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में पेयजल योजना टिक्करी जल भण्डार के निर्माण हेतु ।

संख्या सिंचाई 11-38/2002-मण्डी ।

शिमला-2, 16 मई, 200

जड़ोल	1433/1	0 10 1

यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामत:* भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2 यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है या हो सकते है, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3 पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

अत्यधिक आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

*उप-तहसील कैथू प्रथम, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज नेटवर्क पाईप लाईन के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-33/2002-शिमला।

शिमला-171002, 16 मई, 2002.

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला

उप-महाल	खसरा नं०	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
कैथू प्रथम	92	0	02	46
	94/2	0	14	65
	88/1	0	13	50
	80/1	0	08	25
	90/1	0	12	80
	91/1	0	12	00
	93	0	02	98
	147/1	0	101	52
किता ..	8	0	168	16

*गांव गोल्छा, तहसील व जिला शिमला मे सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-45/2002-शिमला।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
गोल्छा	21	1	12
	22	2	17
	26	2	19
किता ..	3	7	8

तहसील : शिमला (शहरी)

*गांव भराड़ी, तहसील व जिला शिमला में सीवरेज लाईन शिमला शहर के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-32/2002-शिमला।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)	
भराड़ी	485/1	172	37
किता ..	1	172	37

यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत:* भूमि अर्जित करना अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त* प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सोलन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

*गांव बसाल पत्ति कथेड़, तहसील व जिला सोलन मे स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-117/2001-सोलन।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

विस्तृत विवरणी

जिला : सोलन तहसील : सोलन

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)
बसाल पत्ति कथेड़	2116/1392/1073/1	119
	1149/1066/1	55
किता	2	174

तहसील : अर्की

*गांव कोयल मनोग, तहसील अर्की, जिला सोलन में उठाऊ पेयजल योजना टौंस-शील प्रथम चरण पम्प हाउस के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-2/2001-सोलन।

शिमला-2, 16 मई, 2002.

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
कोयल मनोग	203	0	8

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th April, 2002

No. Shram (A)7-1/2002. In exercise of the powers vested in him under section 17(1) of the Industrial Disputes Act 1947, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of awards in the Rajpatra announced by the Presiding Officer, Labour Court of the following cases:-

Sl. No.	Ref. No. Particulars	Section	Remarks
1	2	3	4
1.	Ref. No. 69/2000—Pradhan/Gen. Secy. Emm. Tax Worker Union, Nalagarh *Vs.* M.D. Emm. Tax Synthetics Ltd., Nalagarh.	10	Publication
2.	Ref. 105/1999—Sh. Ashim *Vs.* M/s. Himalyan Forest & Agro Products Barotiwala.	10	-do-
3.	Ref. No. 147/1997—Narain Dass *Vs.* The M.D. Morepen Laboratories Ltd., V.P.O. Mashool Khanna, Parwanoo.	10	-do-
4.	Ref. No. 105/2000 Sh. Sardara Ram *Vs.* M/s. Bitania Chemical Products, Baddi.	10	-do-

1	2	3	4
5.	Ref. No. 166/2000—Sh. Ram Vilas Yadav *Vs.* M/s. Saroo Paper & Allied Pvt. Ltd., Haripur Road, Barotiwala.	10	Publication
6.	Ref No. 81/1999—Sh. Dhana Ram & Om Prakash *Vs.* The Divisional Forest Officer, Paonta Forest Division, Nahan.	10	-do-
7.	Ref. No. 58/1998—Sh. Mohan Lal *Vs.* Executive Engineer, H.P P.W.D, Divn. Haripurdhar, District Kangra & Ors.	10	-do-
8.	Ref. No. 48/1997—Sh. Kashmir Singh *Vs.* B.D.O., Kullu.,	10	-do-
9.	Ref. No. 61/1997—Sh. Daulat Ram *Vs.* HPSEB & Others.	10	-do-
10.	Ref. No. 151/1997—Krishan Singh *Vs.* Ramesh Kumar Bindal, Solan & Others.	10	-do-
11.	Ref. No. 149/1997—Sh. Dilbag Singh *Vs.* Una Distt. Co-operative Marketing & Consumers Fed., Una.	10	-do-
12.	Ref. No. 37/1997-Sh. Tilak Raj *Vs.* The Executive Engineer, H.P.S.E.B. Sirmaur & Others.	10	-do-
13.	Ref. No. 89/2000—Sh. Lekh Ram *Vs.* Cosmo Ferriets Ltd., Jabli, Distt. Solan.	10	-do-
14.	Ref. No. 40/1997—Sh. Dev Raj *Vs.* Chairman Amar Khadi Gramoudyog Samiti, The Mall Solan.	10	-do-
15.	Ref. No. 72/1997-Sh. Raj Kumar *Vs.* Vikas Bybrids and Electronics Ltd., Village Haripur, Solan.	10	Publication

By order.

Sd/-

F.C.-cum Secretary.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. : 69/2000

Decided on : 26-2-2002

Pradhan/Gen. Secy Emm. Tax worker Union Nalagarh .. *Petitioner.*

Vs.

M. D. M/s. Emm. Tax Synthetics Ltd. Nalagarh, Solan (H. P.) .. *Respondent.*

Reference under section 10 *of the Industrial Disputes Act*, 1947.

26-2-2002—Present: None.

Case called thrice, waited for quite some time. It is 2.45 P.M. Still none appeared for the petitioner. It seems that either the petitioner has settled the dispute or is not interested to persue the matter. Hence the reference in the absence of petitioner cannot be answered. Reference is answered in negative. A copy of the order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-

(ARUNA KAPOOR),

Presiding Judge,

H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court Shimla

Ref. : 105/99

Decided on : 26-2-2002

Ashim .. *Petitioner.*

Vs.

M/s Himalyan Forest and Agro Products Barotiwala .. *Respondent.*

Reference under section 10 *of the Industrial Disputes Act*, 1947.

26-2-2002—Present: None.

The case called thrice, waited for quite some time. It is 2.00 P.M. Petitioner despite services not present. It seems that either the petitioner has settled the deispute or is not interested to persue the matter. In the absence of the petitioner, the reference cannot be answered. Hence the reference is answered in negative. Let a copy of this order be sent to appropriate Government.

Sd/-

(ARUNA KAPOOR),

Presiding Judge,

H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H.P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 147 of 1997

Instituted on : 4-10-1997

Decided on : 25-2-2002

Narain Dass s/o Sh. Surat Ram c/o Shri J. C. Bhardwaj, The General Secretary, H. P. AITUC, Saproon, Solan .. *Petitioner.*

Versus

The Managing Director, Morepen Laboratories Limited, V.P.O. Mashool Khanna, *via* Parwanoo, Distt. Solan (H. P.) .. *Respondent.*

Reference under section 10 *of the Industrial Disputes Act*, 1947.

For Petitioner : Shri J. C. Bhardwaj, AR.

For Respondent : Shri S. S. Chauhan, Advocate.

AWARD

This reference has been received from the appropriate government referring the dispute raised by Sh. Narain Dass regarding the termination of his service by M/s Morepen Laboratories. Petitioner has alleged in his claim petition that he was employed by the respondent as Store-keeper on 1-6-1990 and he was thereafter assigned the duties in the security Department. However, his services were dismissed/terminated on 11-3-1997 without any written or speaking order. It is submitted that the termination of service is in violation of mandatory provisions of labour laws and as it has not complied with the provisions of Section 25-F and 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947.

2. Petitioner has also submitted that he has worked for more than 240 days in every calendar year between 1990 to 1997. However, his services have been terminated by adopting hire and fire policy. Therefore, his termination is bad in law and is liable to be set-aside. It is further contended that he is entitled to full back wages, seniority and other incidental benefits.

3. In the reply filed by the respondent, number of preliminary objections have been taken namely that true facts have been suppressed by the petitioner, petitioner has abandoned the job himself and has not been terminated by the management and that despite the orders of the Court, he refused to join the duties. It is also alleged that he is estopped to file this petition on account of his own acts and conducts.

4. On merits, it is submitted that the petitioner was given a job of Store Keeper under severe political pressures though he had no technical qualification. Since his work and conduct was not found satisfactory. & his integrity was doubtful, so he was shifted as Time Keeper, but petitioner was not found regular in his attendance even there and therefore, he was again shifted as Security Guard because the management could not get rid of him due to the political hold. It is, however, submitted that the services of the petitioner were not terminated by the company. Rather on 10-3-1997, petitioner came and approached the Factory Manager and informed him that he has got a very good job, so he would like to leave the job of the respondent. Thereafter, he hosted a party for other workers. It is also submitted that Factory Manager gave him the performa for no dues certificate, but the petitioner thereafter did not return. The management also sent two registered letters to him, but he did not respond to these letters. It is submitted that the service of the petitioner have not been terminated rather he is absconding at his own will. Moreover that wilful absence amounts to abandonment of job. Therefore, he is not entitled to the back wages and petition deserves to be dismissed

5. Replication was also filed by the petitioner, in which all the allegations of the management have been denied by him.

6. On the pleadings of the parties, the following issues were framed on 20-10-2000:—

1. Whether the termination of the petitioner is in violation of Industrial Disputes Act, as alleged ? OPP.
2. Whether the petitioner has abandoned the job as alleged. If so, its effect ? OPR.
3. Relief.

FINDINGS :

7. *Issues* 1 & 2.—I will deal with both the issues together as they require the appriciation of same evidence and law. There are certain admitted facts on record such as that the petitioner joined the respondent on 1-6-1990 and he remained in service till 10-3-1997. Further there is no dispute that during this period, petitioner has not completed 240 days in any calender year. In view of these facts, petitioner is entitled to the compliance of the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, it is found that he was retrenched or terminated by the management.

8. The plea of the respondent is that petitioner was an unwilling worker and had been employed on account of some political pressure. Further that his services were never terminated, but he abandoned the job himself. Therefore, he is not entitled to the back wages though he continue to be an employees of the respondent and can re-join the service of the respondent.

9. In the leght of these submissions, the evidence which has been led by the parties has to be analyzed.

10. Petitioner Narain Dass has appeared in the witness box and alleged that he was dismissed without any reasons. No notice or retrenchment compensation was given to him. He denied that he abandoned the job himself. He has been questioned about this qualifications as Store-Keeper, to which petitioner has replied that though he was not possessing technical qualification for the job, but he had the experience on account of his Army service. He has also mentioned that he did not, receive any registered letters for joining the duties. He has denied that he threw a party on 10-3-1997 and told the management that he has got a very good alternative job and wants to leave the job of the respondent.

11. In rebuttal of this evidence, the respondent has examined three witnesses. Shri Rakesh Sharma is the Assistant Officer of the respondent. He has mentioned that petitioner who was a Security Guard was discharging his duties normally. However, he came and told him that he has got a job elsewhere so he is leaving the job. He also filled a clearance form and Mr. Rakesh Sharma gave him a no objection proforma, which was required to be filled by the various departments. However, thereafter, he (petitioner) did not report back and so two letters were sent to him which have been exhibitted as RW-2/A. & RW-2/B. However, he did not report for duties despite these letters. This witness has mentioned in the cross-examination that the acknowledgement or receipt of the registered letter is not available in the record. He has also mentioned that the letters are just the copies and originals have been sent to the petitioner. He has also mentioned that adverse remarks against the employees are not conveyed to the workers. Lastly he has admitted that no enquiry was conducted against the petitioner after he failed to report for the duty despite letters sent to him nor his dues were sent to him.

12. Sq. Ld. Y. R. Sharma. Assistant Manager of the respondent has mentioned that in January, 1997 he wrote the ACR of the petitioner, the copy of which, is Ex. RW-1/A. Further that petitioner informed him that he is joining another job and so he directed him to report to Personnel Department. He also mentioned that he was told by a Senior Guard that petitioner and two others are having party in the Canteen, which he assumed to be a fairwell party to the petitioner. He has also mentioned that petitioner thereafter did not report to him. He however, admitted that services of the petitioner was not terminated as he had to be terminated only through him. In the corss-examination, he expressed his ignorance as to whether copy of the ACR was sent to him or not. He has also mentioned that to his knowledge, no resignation letter has been tendered by the petitioner.

13. Third witness is Shri Gian Chand who is also working as security Guard and he has mentioned that petitioner informed him on 10-3-1997 that he wants to start his own work and is leaving the job and thereafter, he gave a party and left the job. However, he has mentioned that he is not aware whether any resignation was given by him. He has denied the suggestion that he is deposing wrongly at the instance of the management.

14. The stand of the respondent is not at all clear. The assertion that the petitioner was given the job under political pressure is irrelevant. Rather management is admitting that the jobs are offered not on the basis of qualifications and experience, but under political compulsions. However, this fact is irrelevant for the purpose of deciding the point and the present petition. The management has tried to project that though petitioner was an inefficient, irregular and unwilling worker, but was retained due to his political connections. Again this fact is not relevant for the purpose of deciding the present petition because if the petitioner was not discharging his duties properly, the management could have taken disciplinary action against him and dispensed with his services after holding enquiry etc., which has not been done.

The only fact which is relevant is whether on 10-3-1997 petitioner left the job on his own or whether he was terminated by the management. Admittedly, no resignation letter had been tendered by the petitioner nor he has given anything in wirting that he wants to be relieved from the job. The respondent has tried to prove their version by examining three of their employees, however, they do not inspire confidence. Firstly the version given by RW-2 Shri Rakesh Sharma is that petitioner had certain articles under his charge, which he has not returned and are still pending with the petitioner, whereas RW-1 has mentioned specifically that there were no articles under his charge from the Security Department. Then the ACR which has been allegedly recorded in January, 1997 by RW-1 has not been proved properly. Firstly because the original record has not been produced and secondly the copy of this ACR has not been sent to the petitioner, though it records some adverse remarks against him. Then two registered letters are alleged to have been sent to the petitioner, to join his duties, but neither any receipt nor any acknowledgement nor any official record has been produced to show that these letters were sent through registered post or were sent at all. Rather, RW-1 has mentioned that one of the letters was sent through a Security Guard to deliver it to the petitioner. I fail to understand that if they were registered letters, as is evident from the headings given on the letters Ex. RW-3/A and Ex. RW-3/B. Then how they were delivered personally through a S. Guard. Therefore it appears that all these three documents have been prepared lateron by the management to justify their action. Infact there is no proof that petitioner ever offered to leave the job and left the job on his own.

15. This fact otherwise appears incorrect because had petitioner left the job and had he informed his superiors about the same, then there was no need of sending two registered letters to him for joning the duties. The contents of these letters do not mention that the petitioner had offered to resign from the jobs. Rather it mentioned that petitioner is absent from 11-3-1997 onwards. If it was so, then the management was required to hold an enquiry into the absence and take appropriate action on the basis of the enquiry. However, no such enquiry was conducted regarding this absence.

16. Another factor which is important is that reference has been received in this Court in October, 1997 itself, meaning thereby that the petitioner raised the dispute before the Conciliation officer immediately and he has no intentions of abandoning the job "because had he abandoned the job himself, he would not have raise the dispute immediately. So only inference which can be drawn is that petitioner was neither interested to abandon the job nor abandoned the job himself. I, therefore hold that respondent has failed to prove Issue No. 2, whereas petitioner has proved Issue No. 1 that his services were terminated without complying with the provisions of section 25-F of the Act.

17. The learned counsel for respondent has argued that petitoner has never been terminated and he can join without back wages because due to his absence from duty, he has disentitled himself from claiming the back wages. He has placed reliance on 1997 (3) SCT-186, State of Punjab V/s Om Parkash. In this case, the Court has held that petitioner abandoned the job himself. Therefore it was held that he is not entitled to the back wages. However, in the present case, I have held that the abandonment of job is not proved. Therefore, the authority cited by the learned Counsel for the respondent is not applicable. Another authority cited by him is Recent Service Judgements reported in 2001 (4) RSJ-774. Again the facts of this case are entirely different. The petitioner who was a police Constable had remained absent and circumstances of that case are different and it was held that his absence from duty is a greavest act of misconduct and the order of dismissal was upheld. Again in the present case, abandonment of job or absnece from duty is not proved. I, therefore, hold that the petitioner is entitled to be re-instated in job and he is also entitled to the back wages to the extent of 50% as it is not proved by the respondent that he was gainfully employed during this period. Petitioner is also entitled to the seniority and all other consequential benefits on account of his seniority. The issues are decided accordingly.

RELIEF

18. Keeping in view the aforesaid findings and discussion I hold that the termination of the petitioner is illegal and I order his re-instatement with continuity of service and back wages to the extent of 50% from the date of his disengagement. The reference is answered accordingly. Let a Copy of this award be sent to appropriate government for its publication.

Announced in the Open Court today this 25th Day of February, 2002

Seal.

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H P Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor Presiding Judge, H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. : 195/2000

Decided on : 28-2-2002

Sardara Ram .. *Petitioner.*

Vs.

M/s Bitania Chemical Products, Plot No. 51-53, Industrial Area Baddi, Teh. N/garh, Distt. Solan .. *Respondent.*

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

28-2-2002:—Present:—None for the petitioner.

Sh. Jasbir Singh, AR for the respondent.

Neither the part ies petitioner is being served on the address given in the reference nor the advocate/representative of the petitioner Sh. H.C. Sharma who appeared on 30-7-2001 is putting appearance on behalf of the petitioner. Therefore, there is no one to persue the case on behalf of the petitioner. The summons which had been sent to Sh. H. C. Sharma has been received back with the note that he is not representing the parties. Meaning thereby that there is none to represent the petitioner. Hence the matter cannot proceed further for non prosecution by the petitioner & the reference is therefore answered in negative for non prosecution of the case. A copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-*Labour Court,*
Shimla

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. : 166/2000

Decided on : 28-2-2002

Ram Vilas Yadav ..*Petitioner.*

Vs.

M/s Saroo Paper & Allied Pvt. Ltd., Haripur-Road, B/wala. .. *Respondent.*

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

28-2-2002.—Present: Sh. A. K. Sharma AR for the petitioner.

Sh. S. K. Tayagi, AR for the respondent.

The petitioner has settled the dispute with the management as per settlement. Copy of which is Ex-Px and also as per the statement of ARs of the parties placed on record.

In view of the settlement Ex-Px & statement on oath, the present reference its answered as having been withdrawn. Let a copy of order be sent to appropriate Government.

Seal

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-*Labour Court,*
Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour, Court, Shimla

Ref. : 81/99

Decided on. : 2-3-2002

Dhana Ram & Om Prakash .. *Petitioner.*

Vs.

The Divisional Forest Officer, Paonta Forest Divn. Nahan ..*Respondent.*

Reference under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

2-3-2002. Present : None.

The case called many times. Still none appeared for the parties. It is 3.15 P.M. It appears that either the petitioner has settled the case or is not interested to persue the case.

In the absence of the petitioner, the reference cannot be answered. Hence the reference is answered in negative for non prosecution. Copy of this order be sent to appropriate Government.

Seal.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-*Labour Court,*
Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H. P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 58 of 1998

Instituted on : 12-6-1998

Decided on : 5-3-2002.

1. Shri Mohan Lal son of Shri Chet Singh.
2. Shri Basti Ram son of Shri Bugla Ram.

.. *Petitioners.*

Versus

Executive Engineer, HPPWD, Division, Haripurdhar, Distt. Kangra (H.P.) .. *Respondent.*

Refrence under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

For Petitioners : Shri A. K. Gupta, Advocate.

For Respondent : Shri S. D. Sharma, AR.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate government:

"कि क्या सर्वश्री मोहन लाल एवं बस्ती राम श्रमिकों को अधिशाषी अभियन्ता, हि० प्र० लोक निर्माण विभाग, हरिपुरधार, जिला सिरमौर द्वारा क्रमशः 1-6-1990 व 1-4-1989 से नौकरी से निकाला जाना उचित एवं न्यायसंगत है? यदि नहीं, तो कामगार किस सेवा लाभ व वरिष्ठता के पात्र हैं?"

2. Petitioners have alleged that they have been terminated by the respondent illegally and they are to be re-instated in service. It is contended that they were engaged in the year 1983-84 and had completed more than 240 days, but they were discharged/terminated without following the procedure. Hence, they were entitled to be re-instated with back wages and all consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent preliminary objection has been taken that petitioners time barred.

Second that 240 days have not been completed by the petitioners in any calendar year. So they were not to follow the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Also that petition is bad for non joinder of the necessary parties *i.e.* the state of Himachal Pradesh.

4. On merits, it is contended that petitioners have not completed the mandatory 240 days and have abandoned the job themselves. Therefore, the petition deserves to be dismissed.

5. On the pleadings of the parties, the following issues were framed on 31-7-2000:—

1. Whether the termination of the petitioners from employment *i.e.* in violation of I. D. Act ? OPP.

2. Whether the petition is bad for non joinder of the parties as alleged ? OPR.

3. Relief.

FINDINGS

6. *Issue No.* 1 & 2.—In support of the issues, petitioner No. 1 has stepped into the witness box.

He has mentioned that he completed 240 days and that he was not re-employed though junior persons like Ram Datt and Balak Ram were employed after his termination. However, in the cross-examination it has been suggested that except for working for 60 days in the year, 1987 as per Ex. RA, which is the working days chart, he has never worked with the department. Petitioner has further admitted that he has no document to show that he has completed 240 days.

7. In rebuttal Shri Anil Kumar Sharma Assistant Engineer, Haripurdhar has exhibitted the mandays chart of both the petitioners, which are Ex. RA and Ex. RB, according to which they have not completed 240 days of work in any calendar year. Further that he has mentioned that they had left the job on their own. In the cross examination, he has been put suggestion that there is no record showing that the petitioners abandoned the job themselves. This is the entire evidence.

8. As per documents Ex. RA and Ex. RB, which are the documents regarding the working days of the petitioner , petitioner Mohan Lal has only forded for 60 days in 1987 and petitioners Basti Ram has worked for 58 days in 1988, 88 days in 1986 and 26 days in 1985. None of these petitioners have completed mandatory 240 days. Therefore, as per these documents they were not entitled to the benefits of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. Shri Moan Lal while apppearing ringin the witness box has admitted that he has no proof of having worked with the HPPWD for four years. Therefore, apart from these documents, there is no supporting evidence in this regard. As regards, Basti Ram, he has not even stepped into the witness box. Therefore, the evidence led by the respondent and documents exhibitted by them has to be relied upon. So, I hold that the petitioners have failed to prove that they have worked for more than 240 days and they were entitled to any notice or compliance. I, therefore, decide this issue against the petitioners.

9. *Issue No.* 2.—This issue has not been pressed by the parties. Therefore, it is decided against the respondent.

RELIEF

10. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the petitioners are not entitled to any relief and the reference is answered accordingly in negative. Let a copy of this award be sent to the appropriate government for its publication in the H. P. Rajpatra.

Announced in the Open Court today this 5th Day of March, 2002.

Sd/-
Seal. (ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tridunal-cum-Labour Court, Shim

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor Presiding Judge H. P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 48 of 1997

Instituted on : 13-3-1997

Decided on : 6-3-2002

Kashmir Singh .. *Petitioner.*

Versus

1. State of Himachal Pradesh through the Secretary (Development) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.

2. Block Development Officer, Naggar Block, District Kullu (H. P.) .. *Respondent*

Application under Section 33-C (2) *of the Industrial Disputes Act*, 1947.

For petitioner. Shri Sanjay Mandiyal, Advocate.

For respondent : Shri M. K. Pandit, Advocate.

ORDER

Petitioner has mentioned that he was employed by the Block Development Officer, Nagar, District Kullu on daily wages and he was to be paid the wages as per the Goverament rules, which were Rs. 102/- per day, but he was paid the wages at the rate of Rs. 50/- per day only from April, 1992 to May, 1993. Further that from June, 1993 to January, 1994, he was not given the wages for 93 days, which he is entitled to @ Rs. 109.80 paise. Lastly that he has not been paid the wages from February, 1994 to December, 1994. So, he is entitled to an amount of Rs. 68,960.20.

2. In the reply filed by the respondent, it is submitted that petition is not maintainable as there is no settlement or agreement between the parties.

3. On merits, it is mentioned that the petitioner has been paid as per the wages due to him and nothing is due from the respondent. Hence, that the petition deserves to be dismissed.

4. On the pleadings of the parties, the following issues were framed by my learned predecessor on 27-11-1997:—

1. Whether the petitioner is entitled to Rs. 68,962/- as arrears of wages *w.e.f.* April, 1992 till December, 1994 as explained in the application ? OPP.

2. Whether the present application is not maintainable on the grounds as alleged in the preliminary objection ? OPR.

3. Whether this Court has no jurisdiction to entertain, try and decide the present controversy as alleged ? OPR.

4. Relief.

FINDINGS

5. *Issue No.* 1.—Petitioner has mentioned that he was appointed as Junior Engineer on daily wages and joined on 18-11-1991. Further that he remained as Surveyor till 31-3-1992 and thereafter was working

as Junior Engineer from 1-4-1992 to January, 1994 and he was being paid the wages @ Rs. 55/- per day till 1993 though he was entitled to the wages @ Rs. 102/- per day. Petitioner has further mentioned that in May and June, 1993, muster roll was issued for only 19 days and then he was terminated in March, 1994, but he joined the duties on 29-3-1994 as per the stay granted by the Administrative Tribunal. But he was not paid the salary. So he filed the contempt petition and ultimately left the job in December, 1994. He admitted that no written appointment letter as JE was issued to him. He has denied that he worked only as beldar.

6. His statement has been recorded twice. Once when Respondent No. 2 was proceeded against *ex parte* and then after the *ex parte* was set-aside by my learned predecessor.

7. In rebuttal of this evidence Shri Surinder Maltoo, BDO Naggar has appeared and he has mentioned that petitioner was initially appointed as work-charged Surveyor and was paid @Rs. 35/- per day. However as and when some projects were received, petitioner was given employment against the said work. Thereafter, he filed a petition before the Administrative Tribunal, but the case was dismissed as withdrawn on 27-2-1997 though before that a stay had been granted by the Administrative Tribunal that he should be engaged in the same capacity, if vacancy is available. It is mentioned that in persuance to the order of the Administrative Tribunal, joining report was submitted by the petitioner, but since the BDO was not competent, so the Director was approached. However, he was not kept. The documents like the stay order of the Administrative Tribunal, copy of the judgment, joining report and the details of the work awarded has been exhibitted as Ex. R-2 to Ex. R-5. He has also mentioned in his examination in chief itself that petitioner initially was shown Surveyor in the muster roll and lateron he was shown as JE, though he did not work as JE. He has mentioned that it appears to be a Clerical mistake. In the cross-examination, he admits that he was paid the wages of JE as per Chart Ex. PX/1, but the rate was Rs. 50/- per day. He has also mentioned that he is not aware that as per the notification of the Government, the minimum wages of Rs. 102/- was to be paid. The notification has been exhibitted as Ex. PX/2 another notification has been put to the witness which is Ex. PX/3 *vide* which the wages were revised to Rs. 109.80 paise subsequently. Petitioner has also admitted that the muster roll of JE was given to him as per Mark. 1. He has mentioned that as per the record, no work was available, but has no personal knowledge about the same.

8. The evidence which has come on record and the documents which have been exhibitted belies the contention of the respondent that petitioner was never employed as JE. The explanation given by RW-1 that by mistake musterroll of JE was issued cannot be accepted. Moreover, in Ex. PX/1, the details of the muster roll issued to Kashmir Singh petitioner have been mentioned in which he has been shown to be working as JE on the dates specified in this annexure. There is no cross-examination regarding this document that the same has not been prepared correctly as per the record. Therefore, it appears that petitioner was employed as JE as per this Annexure R-1 and he worked as such. However, he was only paid Rs. 50/- per day instead of the minimum wages which were to be paid as per the notification of the Government which has also been exhibitted as Ex. PX R 2 and Ex. PX/3. I, therefore, hold that the petitioner is entitled to the difference of wages for the period as per Annexure PX-1 to Ex. PX/3.

9. Next contention which is raised by the petitioner is that he was disengaged in March, 1994, but then obtained the stay order from the Administrative Tribunal and he submitted his joining report to the respondent. These facts are also not denied by the respondent, rather they have appended the copy of the stay order, which is Ex. R-2. It has also been admitted that joining report was submitted by the petitioner to them. The petitioner, therefore has acted as per the order of the Administrative Tribunal. He submitted his joining report and was to be employed by the respondent in terms of the order Ex. R-2. The warding of this order is reproduced as below:—

> "The respondents are directed to re-engage the applicant in the same capacity preferably at the same place or in the vicinity where the work is available, as on February 28, 1994."

10. This order shows that the directions of the Administrative Tribunal cannot be interpretted to man that petitioner was only to be engaged if the work was available, rather the order only qualified that he should be engaged preferably on the same place and in the same vicinity and in the same capacity, where he was working in February, 1994 or where the work is available. This shows that unless until the respondent got the order modified from the Administrative Tribunal, it was under obligation to appoint the petitioner at a place he was working on 28-2-1994. Now chart Ex. PX 1 show that petitioner was working as Tracer Draughtsman till 24-2-1994. It does not show that petitioner was working in any capacity on 28-2-1994 and on the most it can be interpretted to me that the petitioner was working as Trace Draughtsman on 24-2-1994 and the Administrative Tribunal directed his employment as Tracer Draughtsman. Therefore, the interpretation of this order is that irrespective of the availability of the post, petitioner was to be re-engaged in the same capacity in which he was working on 28-2-1994.

11. On its own saying, the petitioner has mentioned that he resigned in December, 1994. So in these circumstance, the petitioner is entitled to the pay and wages from the date of the order passed by the Administrative Tribunal till December, 1994 of the post on which he was working till 28-2-1994. The respondent is directed to pay this amount to the petitioner if he was in employment on 28-2-1994. Since this order was in operation till December, 1994 and MA was dismissed as withdrawn in 1997 *vide* Ex. R-4. So, I hold that petitioner is entitled to the difference of wages as mentioned above & the wages from 2-4-1994 to 31-12-1994 and against the post which he was holding on 28-2-1994 *i.e.* if any such post was being held by the petitioner.

12. *Issues* 2 & 3.—Both these issues have not been pressed by the parties during the course of arguments. Hence, these issues are decided against the respondent accordingly.

RELIEF

13. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the petitioner is entitled to the difference of wages as JE on the basis of minimum wages prevelant at that time and the wages from 2-4-1994 to 31-12-1994 at the rate and against the post which he was holding on 28-2-1994. This amount be paid to the petitioner within 90 days from the announcement of this order. The case file after its completion be consigned to record room.

Announced in the Opon Court today this 6th Day of March, 2002.

Sd/-
(ARUNA KAPOOR),
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-*Labour Court,*
Shimla.

Seal.

In the Court of Mrs Aruna Kapoor Presiding Judge/ H. P. Labour Court, Shimla.

Ref. No. : 61 of 1997
Instituted on : 28-4-1997
Decided on : 14-3-2002

1. Sh. Daulat Ram s/o Sh. Bansi Ram,
2. Sh. Dhanvir Singh s/o Sh. Inder Singh,
3. Sh. Sunder Singh s/o Sh. Sohan Singh,

4. Sh. Jagmohan Singh s/o Sh. Roop Singh.
5. Sh. Kalam Singh s/o Sh. Amar Singh.
6. Sh. Liaq Ram son of Shri Todiya Ram. ... *Petitioners.*

Versus

1. H.P. State Electricity Board through its Secretary, Headquarters at Shimla.
2. Executive Engineer, HPSEB, Nahan, District Sirmaur (H.P.) ... *Respondents.*

Reference under Section 10 *of the Industrial Disputes Act.* 1947.

For petitioners ; Shri A. K. Gupta Avocate.

For respondents : Shri S. P. Sharma, AR.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate Government;—

> "Whether the termination of services of Shri Daulat Ram and 5 other workers (List enclosed) by the Executive Engineer Himachal Pradesh State Electricity Board, Nahan, District Sirmaur, (H.P.) without any notice, charge-sheet, enquiry and without compliance of Section 25 (F) of the Industrial Diputes Act, 1947 on completion of 240 days' service is legal and justified, if not, to what relief of service benefits including back wages, seniority and amount of compensation, the aggrieved workmen are entitled ?"

2. Petitioners have filed a joint petition alleging therein that they were working as T-Mates, beldars with the respondents. However, their services were terminated without complying with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947, though they had completed 240 days of service in the calendar year. As an alternative it has been mentioned that even if they had worked for less time, they were entitled to 10 days notice as per the Certified Standing Orders. It is also contended that principle of last come first go was not adhered to and so they are entitled to re-instatement with consequential benefits and back wages etc.

3. In the reply filed by the respondent, preliminary objection has been raised that the claim is belated. There is no legally enforciable cause of action against the respondent.

4. On merits, it is mentioned that petitioners have not completed 240 days of employment in any of the calendar years. Rather they were working casually and so the provisions of section 25-F of the Industrial Disputes Act and 25-J are not attracted. Similarly that the provisions of Certified Standing Orders are also not applicable as they have not completed 240 days of service in any of the Calendar years. Hence petition deserves to be dismissed.

5. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 3-7-1998:—

1. Whether the termination of the services of petitioners is illegal and bad in law in view of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 and in view of Standing Orders. If so, its effect ..OPP.
2. Whether the petition is barred by laches and delays ? If so, its effect ..OPR
3. Relief.

FINDINGS

6. *Issue No.* 1.—The petitioners have taken a plea firstly that they have completed 240 days of employment in the calendar year and so they were entitled to a notice under Section 25-F of the Act alongwith retrenchment compensation before their services could be terminated. In the alternative they have taken the plea that even if they have not completed 240 they were still entitled to a notice of 10 days as per the Certified Standing Orders as it has been made applicable to the respondent in the year 1985 and since no such notices have been served on them. So they are liable to be re-instated.

7. On the other hand, the plea of the respondent is firstly that their services have not been terminated rather that they abandoned the job themselves and secondly that they have not completed 240 days in the calendar year and they are not covered under Section 25-F of the I. D. Act and the certified Standing Orders. Hence, they are not entitled to the relief claimed by them.

8. The plea of the abandonment is not at all proved by the respondent. Rather Shri Lal Chand Pardeshi who is Assistant Engineer and appeared as RW-1 has mentioned that as per their record, it does not appear that petitioners have abandoned the job themselves nor it can be assumed that they have been terminated. Again in cross-examination he has mentioned that there is no record to show that petitioners have abandoned the job themselves. Therefore, the plea of abandonment is not proved even as per the evidence of the respondent themselves and the petitioners namely Dhanvir Singh, Daulat Ram and Sunder Singh who have appeared in the witness box have categoryically denied that they left the job on their own. I, therefore, hold that the services of the petitioners were terminated by the respondent.

9. Now coming to the plea of completion of 240 days in a calendar year, the petitioners have not provided any documentary evidence except their own statements on oath. However, the record which has been produced by the respondent, which is Ex. R-1 to Ex. R-6 shows that petitioners have not completed 240 days in the calendar year preceding their termination. I, however, would like to mention the chart which has been sent to the Counciliation Officer and it has been appended as Annexure with reference mentions specifically that all the workers have completed services of 240 days. Another factor which is relevant is that the record of the respondent got burnt in the year, 1990 and whatever record has been produced by them has been prepared on the basis of the cash book etc., but the copies of such cash books has not been produced in the Court. Therefore, much reliance cannot be placed. On the document; Ex. R-1 to Ex. R-6 because they have been prepared on the basis of some other record and neither that other record has been produced nor the person who has prepared such record has been examined to prove the authenticity of the documents which have been produce Ex. R-1 to Ex. R-6. Neither of the parties has examined the record of the Conciliation Officer to ascertain the basis of his note in the Annexure, in which it is mentioned that all the petitioners have completed 240 days of work in a calendar year. So, the evidence which has some on record is highly unsatisfactory, vogue and inconclusive.

10. An alternative plea has been raised by the petitioner that they were entitled to 10 days notice as per the Certified Standing Orders, which fact is not disputed. As per the Certified Standing Orders, petitioners were entitled to 10 days notice even if they had not completed 240 days of work in an year. RW has admitted that no such notice was served. It is even not disputed at the time of arguments that Certified Standing Orders were applicable and no such notice has been sent as per the Certified Standing Orders. Therefore, even if it is assumed that the petitioners have not completed 240 days in the calendar year preceeding their termination can be held illegal for violation of Certified Standing Orders regarding

which specific issue has been framed by my learned predecessor. So, I hold that the termination of the petitioners is illegal and unjustified in view of the Certified Standing Orders.

11. Petitioner Daulat Ram has been terminated in 1987, Liaq Ram has been terminated in 1993 and other petitioners have been terminated in the year, 1995, but the reference has been received in this Court only in 1997. In the circumstances, the re-instatement of petitioners can only be ordered from the date of the reference in this Court. There is nothing on record to prove that the petitioners were not gainfully employed during this period, even petitioners have not mentioned in their statements that they were not gainfully employed during this period. Therefore, they are not entitled to the back wages. I, therefore, hold that petitioners are entitled to be re-instated in service from the date of reference without any back wages, but with the benefit of continuity and seniority of service from the date of reference. Issue is decided accordingly.

12. *Issue No.* 2.—This issue has not been pressed by the parties during the course of argument, hence decided against the respondents.

RELIEF

13. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the petitioners are entitled to be re-instated in job with continuity and seniority but without back wages from the date of the reference. Reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate Government.

Announced in the Open Court today this 14th day of March, 2002.

Seal.

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge, H.P. Labour Court, Shimla

Ref. No. 151 of 1997

Instituted on : 20-11-1997

Decided on : 14-3-2002

Krishan Singh son of Shri Chet Ram, Village Kathed, P.O- Chambaghat, District Solan, H. P. ..*Petitioner.*

Versus

Ramesh Kumar Bindal and Ram Kumar Bindal, Prop. M/s Vaid Bal Mukand and Sons, Main Bazar, Solan, H.P. .. *Respondent.*

Reference under Section 10 *of the Industrial Disputes Act,* 1947.

For petitioner ; Shri J. C. Bhardwaj. AR.

For respondent : Shri V. K. Gupta, AR.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate Government:—

"कि क्या कामगार श्री कृष्ण सिंह को नियोजक श्री रमेश कुमार बिन्दल एवं राम कुमार बिन्दल मालिक मै0 वैद्य बाल मुकुन्द एण्ड संज, मुख्य बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा नौकरी से निष्कासित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है ? यदि नहीं तो कामगार किस क्षतिपूर्ति, सेवा लाभ व वरिष्ठता का पात्र है ?"

2. In the claim petition filed by the petitioner, it is alleged that petitioner was employed as Manual worker and as Packer in Bindal Basayan Shala in February, 1987 and he worked in the said establishment till his illegal termination on 18-11-1996. It is submitted that petitioner was shifted to the shop of the said establishment in 1991 and he has been working in the shop till his termination. It is also submitted that he completed 240 days in every calendar year and was covered under Section 25-B of the Industrial Disputes Act, 1947. However, his services were terminated without serving any notice without paying any compensation as required under the law. Hence his terminatiion is illegal and against the provisions of Section 25-F of the I.D. Act.

3. Petitioner alleges that he was drawing Rs. 1680/- per month at the time of his termination. However, he was not being given weekly rests and other leaves provided nor he was given sick leave, earned leave or the Festival holidays. Hence, he is entitled to be re-instated in service with full back wages and all other service benefits.

4. In the reply filed by the respondent, preliminary objections have been taken that there are less than 8 workers in the establishment and therefore, it is not covered under the Industrial Disputes Act.

5. On merits, it is contended that petitioner worked with the respondent only for about 4 years and thereafter he left the services on his own. It is also contended that there was no termination on the part of the respondent. It is further submitted that even during the employment with respondent, petitioner was running his own business of purchase and sale of 'Pahari goods' and was earning good money from this business. It is further submitted that petitioner owns 100 bighas of land in Solan and is a progressive farmer and he also left the job for better prosepectus. It is cantended that the petitioner was being paid Rs. 1400/- per month and not Rs. 1680/- per month as claimed by him that he was being given weekly rests as required under the law. Therefore, the petition may be dismissed.

6. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 20-11-1998:—

1. Whether the termination of petitioner is illegal and bad in law in view of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, if so its effect ? OPP.

2. Relief.

7. *Issue No.* 1.—To prove the rival contentions, petitioner has stepped into the witness box himself, whereas on behalf of the respondent, three witness have appeared including one of the partners of the respondent concern.

8. The main contention of the petitioner is that respondent is an industrial establishment and he being a workman and having completed 240 days of employment in every calendar year, could not have been terminated by the respondent without complying with the provisions of Section 25-F of the Act. On the other hand, the contention of the respondent is that firstly respondent is not an establishment covered under the Industrial Disputes Act as it has less than 8 workers working under it, secondly that the petitioner abandoned the job himself as he was having a good business of his own and therefore, he was not terminated by the respondent. Rather, the petitioner was also given an offer to join the respondent during the conciliation proceedings, but the petitioner refused to do so. Therefore, petitioner is not entitled to any benefits claimed by him.

9. To appriciate the rival contention, the evidence both oral as well as documentary has to be appriciated. Coming to the petitioner's submission as to whether the respondent is an industrial establishment or not, there is not much of evidence led by the parties. The

respondent has submitted that there are about 14 workers working in three different establishments, but all these three are different entities. However, no documentary evidence in support of this contention has been brought by them. On the other hand, the worker's contention is that Bindal Rasam Shala, the Shop establishment by the name of M/s Bal Mukand and Sons and Bal Mukand Udyog are concerns owned by same persons and is a single unit. Since, no documentary evidence has been led by the parties, therefore, in the absence of any documentary proof regarding the registration of these concerns, the only inference which can be drawn is that all the three concerns are one industrial establishment (as all these concerns are owned by the same owner) and no proof of the separate registration has been produced by the respondents, how in natural course and must be in possession of the record) in which admittedly, 14 workers are working. Therefore, I hold that the respondent concern is an industrial unit covered under the Industrial Disputes Act and petitioner was a workman employed by this unit.

10. There is no dispute that petitioner had completed 240 days of working in the calendar years during which he was employed by the respondent. The only point when requires to be appreciated is whether the services of the petitioner has been terminated in violation of section 25-F of the Act or not. Though the respondent had taken the plea of abandonment of service, but the plea regarding abandonment has not been referred to this Court for adjudication. The petitioner has cited various authorities that the Labour Court cannot go beyond the scope of reference and so no adjudication can be given regarding the abandonment of service by the respondent. However, the respondent has also cited authorities showing that the plea of abandonment can be appreciated by the Labour Court and has relied upon the Judgment of Hon'ble High Court delivered in CWP No. 369 of 1996 titled as Sidhartha Supri Spinning Mills Ltd. v/s State of H.P. and others. In the judgment Hon'ble High Court has held that an issue about the abandonment of job had been framed by the Labour Court on the pleadings of the parties and parties had subjected themselves for the adjudication of the dispute on this point. Therefore, the decision of the Labour Court on this issue cannot be considered to be an extraneous matter. Para-7 of the judgment is reproduced as below:

> "The second contention is that the Labour Court had no jurisdiction to travel beyond the reference and the only question which it could have decided related to termination of the workers by the petitioner on 4-7-1993 and it could not have gone into the question of abandonment of the job by the workers. There is absolutely no meritin this contention. It is only at the instance of the petitioner that the Labour Court has framed the issue regarding the abandonment and considered it on merits. Having failed on the consideration of the Labour Court of the said question, it is not open to the petitioner to contend that the Labour Court travelled beyond the scope of the reference."

11. However, in the present case, no issue has been framed on the specific plea of abandonment raised by the respondent but the plea that the petitioner himself left the job after orally intimating the respondent can be appreciated in order to arrive at the finding whether the services of the petitioner was terminated by the respondent or not.

12. I may mention that there is no evidence on record respondent served any notice on the petitioner either to rejoin duties or to ask for his explanation as to why he is absenting from his duties. It is also admitted that no compensation was offered or paid to the petitioner by the respondent. Therefore, the compliance of Section 25-F of the Act has not admittedly been made abandonment is not framed. The only plea which requires to be appreciated is whether petitioner expressed his intention of leaving the job or not. To prove this fact, respondent has relied upon the statement of one of the partners Shri Ram Kumar Bindal and Ex. R8, which is the copy of the Register of employees, in which a note has been given that petitioner has left the job. However, since this document is only an admission in favour of the respondent itself was in custody of the respondent, it does not carry much value and under the circumstances, except the statement of Shri Ram Kumar Bindal, there is no other evidence of any other worker working in the shop or any other person to show that the petitioner expressed his intention of leaving the job. So this plea of the respondent is not proved so only conclusion which can be drawn is that the services of the petitioner was terminated and the provisions of section 25-F of the act was not complied with. Therefore, the termination can be held to be illegal and against the provisions of law.

13. The second plea of the respondent is that the petitioner was not at all terminated and he is still at liberty to join the duties and in fact such offer was made even in the presence of the Conciliation Officer. In support of this plea the proceedings before the Conciliation Officer has been exhibitted by the petitioner where the Conciliation Officer has recorded that respondent has made an offer to the petitioner to again keep him in job, but the petitioner refused to accept the offer, unless, he is paid back wages and he is compensated for the holidays and he is given other leave benefits etc. So the question which now survives for consideration is on what terms and conditions, the petitioner can be reinstated in service. Again both the parties have relied upon various judgments in support of their contentions. The respondent had led evidence to show that petitioner who has about 100 bighas of land and is running a shop in which he is selling things of daily needs is gainfully employed and so he is not entitled to back wages. Again though oral evidence has been led by the respondent to prove that a shop is being run by the petitioner, no documentary evidence has been produced. Two witnesses Shri Shashi Bhushan Singh and Shri Faquir Chand have though deposed that they have seen petitioner running the kiryana Shop at Kathar, but their statements do not inspire much confidence. Both of them..... are casual witnesses and their statements have to be appreciated in the light of the cross-examination done on them. Shri Faquir Chand has admitted that he just came to know by chance about the litigation and decided to depose in favour of the respondent and Shri Shashi Bhushan Singh has admitted that his brother had been working for the respondent and that he does not know why Mr. Bindal contacted him to deposit in the case. The fact however remains that even the petitioner has admitted that he is running a small shop, where he is selling the produce of his own land holding. However, his contention is that this type of income is not a gainful employment for the purpose of denying the back wages to him. In this regard, he has relied upon 1999-LLR-877, in which Hon'ble Bombay High Court has held that a person working on his own agricultural farm and earning Rs. 100 per day cannot be equated with gainfull employment and the claim of the petitioner that back wages cannot be rejected on that ground. In another case Hon'ble the Supreme Court of India has held, which is reported in 1991-LLR-541 that a petitioner who after the termination of his services started practising as a lawyer can be granted back wages, the relevant para is reproduced below:

> "The petitioner cannot be denied back wages simply on the ground that he was practising lawyer during the relevant period. However, his probable income shall have to be taken into account for computing back wages. In the instant case in the affidavits filed by the petitioner it is stated that he was practising as an income tax advocate ever since his enrolment in October, 1982. But, however he asserted that he got his

first brief in the year, 1985. These averments are contradicted by the other side. Under These averments are contradicted by the other side. Under these circumstances the Court cannot for the Corporation to unearth the income which the petitioner would have derived as a practising advocate. There are many imponderables and conjectures too. Under these circumstances, the Court asked both the counsels to suggest a solution. The learned counsel for the petitioner submitted that even if the relevant period is to be treated as one of the suspension pending enquiry the petitioner would have been entitled to the subsistence allowance till his reinstatement. That atleast should be the criterion in granting the back wages, in a situation like this."

14. In another judgment delivered by Hon'ble Punjab and Harayana High Court reported in 1998 LLR-478, it was held that denial of back wages on the plea that workman was doing agricultural operation for earning his livlihood is wrong and cannot be equated with gainful employment and to claim of the workman for back wages cannot be rejected.

15. Considering these authorities and applying the law laid down to the facts of the present case, it can be safely held that self-employment in one's own land holding cannot be treated to be a gainful employment. However, the extent of payment of back wages can be determined on the reasonable assessment of the income being generated by the petition by such self employment and quantom of back wages can be fixed accordingly. In this regard, I find support from the judgment delivered by Hon'ble Supreme Court cited above.

16. It is clear from the observations made by the Hon'ble the Supreme Court that the probable income can be taken into account for computing back wages. In the light of these observations a reasonable estimate of the income of the petitioner has to be made from the evidence which has been led by the parties. As I have already said that the petitioner has admitted that he has a small shop where he is selling things and produce of his own field and though respondents plea is that he is a big farmer owning 100 bighas of land and running a successful business of a Kiryana Shop, has not been able to prove the actual income from these sources. As such, in these circumstances, I hold that the petitioner can be held to be entitled to 20% of the back wages for the period of his disengagement/ termination, which is 18-11-1996 to the date of the award. The petitioner is also entitled to other benefits like the seniority etc. I, therefore, decide this issue accordingly.

RELIEF

17. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the termination of the petitioner is illegal and I order his re-instatement with back wages to the extent of 20% for the period of his disengagement/termination *i. e.* from 18-11-1996 to the date of the award. The petitioner is also entitled to other benefits like the seniority continuity of service *w.e.f.* 13-11-96. The reference is answered in affirmative. Let a copy of this award be sent to appropriate Government for its publication in the H.P. Rajpatra.

Announced in the Open Court today this 14th day of March, 2002.

Seal.

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H.P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Mrs. Aruna Kapoor, Presiding Judge H.P. Labour Court, Shimla

Ref. No. : 149 of 1997.

Instituted on : 11-11-97

Decided on : 14-3-2002

Shri Dilbag Singh son of Shri Bhagat Ram, V.P.O. Jalanga Tavaa, Tehsil & District Una, H.P. .. *Petitioner*

Versus

The Una District Co-operative Marketing and Consumers Federation Una, H.P. through its Managing Director .. *Respondent*

Reference under Section 10 of the Industrials Disputes Act, 1947.

For petitioner: Shri Hem Raj, AR.

For respondent: Shri Sohan Lal, AR.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate government:

"क्या श्री दिलबाग सिंह पुत्र श्री भगत राम, गांव व डाकखाना जलगां टब्बा, तहसील व जिला ऊना की प्रबन्ध निदेशक, दी ऊना जिला सहकारी विपणन एवम् उपभोक्ता फैडरेशन, ऊना द्वारा 31-03-1997 से नौकरी से निकाला जाना उचित व न्यायोचित है? यदि नहीं तो श्री दिलबाग सिंह किस राहत एवं सेवा लाभों का हकदार है?"

In the claim petition filed by the petitioner, it is alleged that he was working with the respondent and his services were terminated *w. e. f.* 30-3-1997. He was not given one month's notice nor he was paid any salary in lieu of the notice and he was also not given the retrenchment compensation. So his termination is illegal and he is liable to be re-instated with back wages and all other consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent three preliminary objections have been raised. Firstly that the petitioner has not sought the remedy under the H.P. Co-operative Societies Act, 1968. Secondly that he is estopped to file the present claim petition by his own acts and conducts and thirdly that the application has not been preferred before the proper forum.

4. On merits, it is contended that the petitioner was appointed as Salesman on daily wages on 1-7-1988 and he worked till 31-3-1997. Further that he was served with one month's notice on 11-6-1996. It is submitted that the services of the petitioner was terminated because the work relating to the distribution of essential commodities was transferred from the replying respondent to the H.P. State Civil Supplies Corporation after obtaining the approval from the Additional Registrar, Co-operative Societies. It is also submitted that the petitioner has concealed the material fact as he had challenged the notice served on him unsuccessfully before the H.P. Administrative Tribunal. It is also submitted that the Federation is under Liquidation due to financial crises. Hence, the claim of the petitioner deserves to be dismissed.

5. On the pleadings of the parties, the following issues were framed on 28-7-2000:

1. Whether the dismissal of Dilbag Singh from the service by the respondent is against the Industrial Disputes Act,? If so, its effect? .. OPP
2. Whether the petitioner is not maintainable in view of the preliminary objection? .. OPR.
3. Relief.

FINDINGS

6. *Issue* 1 & 2.- Evidence was led by the petitioner, but the respondent did not lead any evidence. Arguments were heard. No doubt objection has been raised by the respondent that it is the Society registered under the Co-operative Societies Act, 1968, but there is nothing on record to prove this contention. So much so that no oral or documentary evidence has been led nor the petitioner has been cross-examined on this line when he appeared in the witness box. In the reply this contention has been raised, but it is not established. The judgment of H.P. Administrative Tribunal has been filed as Annexure E and it shows that a notice was issued on 11-6-1996 for terminating the service of the petitioner for the reasons that the work of distribution of essential commodities had been transferred to H.P. State Civil Supplies Corporation and so the services of the petitioner were no longer required. This notice was challenged by the petitioner though un-successfully before the Administrative Tribunal and the notice was held to be invalid by the Administrative Tribunal *vide* its order dated 11-1-1997. Thereafter, petitioner continued to be in service even after the expiry of the said notice and the decision of the Administrative Tribunal and no further notice was served on his coinciding with his termination on 31-3-1997. Therefore, neither the respondent has been able to establish that it is a company registered under the Co-operative Societies Act nor it has been able to prove that any notice was served on the petitioner under section 25-F of the Industrial Disputes Act. Hence, the termination of the petitioner on 31-3-1997 cannot be held to be valid and legal. Moreover Hon'ble the Supreme Court has held in Agricultural Produce Market Committee and Other *v/s* Ashok Harakuni and Others reported in 2000(*ii*) LLJ-1382 that merely the fact that employees of the Committee are Government servants is not crucial, rather the true test is dominant object for which functionaries are working and if they were held not to be performing sovereign functions, the the Committee falls within the definition of 'Industry'. In this case, even if it is assumed that the society is registered under the Co-operative Societies Act, yet is not established that Committee was performing sovereign functions and not indulging in the business or the activities. Hon'ble the Supreme Court as defined the term 'industry' in Bangalore Water Supply & Sewerage Board, *Vs.* R. Rajappa & Otrs reported in 1978-I-LLJ-349. Therefore, applying these tests to the present case, it can be safely held that the activities of the Society involved the selling and distribution of consumer items and petitioner was appointed as Salesman to undertake the activity, therefore, the function of the society was more close to that of a industry. Therefore, the petitioner who was working in this society was a workman and covered under the Industrial Disputes Act and so he was entitled to the notice and retrenchment compensation, which has not been paid to him. The petitioner has stated on oath that no retrenchment compensation was paid to him nor he was given the leave encashment, which statement has gone unchallenged. Therefore, I hold that the termination of the petitioner is illegal and not in accordance with Section 25-F of the Act.

7. Now coming to the question of benefits apart from the re-instatement. Petitioner has kept quite regarding being unemployed during all this period. Neither in his petitioner in his statement has he mentioned that he was not gainfully employed during this period. Therefore, in the facts and circumstances of the case, it appears proper to allow him seniority and continuity of service from the date of termination, but he is not entitled to the back wages for this period. Hence, both these issues are decided in favour of the petitioner.

RELIEF

8. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I held that the petitioner is entitled to be re-instated in service with seniority and continuity but without back wages. The reference is answered in affirimative Let a copy of this award be sent to appropriate Government.

Announced in Open Court today this 14th day of March, 2002.

Seal.

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court,
Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge Himachal Pradesh Labour Court, Shimla

Ref. No : 37 of 1997

Instituted on : 17-3-1997

Decided on : 15-3-2002

1. Shri Tilak Raj son of Shri Hirda Ram.
2. Shri Khayalu Ram.
3. Shri Tula Ram son of Shri Shri Ram.
4. Shri Amar Singh son of Shri Chamel Singh.
5. Shri Nita Ram Son of Shri Nanta Ram.
6. Shri Pritam Singh son of Shri Chet Ram.
7. Shri Ranjit Singh son of Shri Prithvi Singh.
8. Shri Prem Singh son of Shri Sobha Ram

.. *Petitioners.*

Versus

The Executive Engineer, H. P. S. E. B. (Electrical), Division, Nahan, District Sirmaour, Himachal Pradesh .. *Respondent.*

Reference under Section 10 *of the Industrial Disputes Act*, 1947

For petitioners : Shri A. K. Gupta, Advocate.

For respondent : Shri S. P. Sharma, A. R.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate Government :—

"Where the termination of services of Shri Tilak Raj and 9 other workers (list enclosed) by the Executive Engineer, Himachal Pradesh State Electricity Board, Electricial Division, Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 on completion of 240 days continuous service is legal and justified, if not to what relief of service benefits including back wages, seniority and amount of compensation, the aggrieved workmen are entitled ?".

2. Eight of the petitioners mentioned in the reference out of 10 have filed the claim petition and alleged therein that they were working with the respondent though they had completed 240 days of service in the calendar year, but their services have been terminated without serving any notice or payment of retrenchement compensation. Further that even the compliance of Certified Standing Orders has not been made through they are applicable to the petitioners. It is submitted that in case petitioners were held not to have completed 240 days of service in the calendar year, still they were entitled to a 10 days notice as per the Certified Standing Orders, which were not given. Hence, the petitioner are entitled to be re-instated in service with all consequential benefits like seniority and back wages.

3. In the reply filed by the respondent, three preliminary objections have been raised. Firstly that the petitioners has no enforciable cause of action, petition is bad for want of better particulars and that the claim is belated.

4. On merits, it is submitted that though the petitioners were working for the respondent, but they were very casual in their work and none of them have completed 240 days of working in any calendar year. So they were not entitled to any notice or retrenchment compensation. It is also submitted that petitioners left the service on their own and were not terminated by the respondent.

5. On the pleadings of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 12-11-1997:

1. Whether the termination of the services of the petitioners by the respondent Board is violative of Section 25-F of the Industrial Disputss Act, 1947 and on the other grounds as alleged ? . OPP.
2. Whether the petitioners has no enforciable cause of action as alleged ? .. OPR.
3. Whether the application suffers from laches and delays ? .. OPR.
4. Relief.

FINDINGS

6. *Issue No.*1.—Three of the petitioners have appeard in case witness box in support of their case. Shri Tilak Raj, Ranjit Singh and Pritam Singh have stated that they have completed 240 days and that they did not leave the job on their own, but they were terminated by the respondent without compliance of the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. Suggestion which has been given to them are that they never made any representation to the department and they have not completed 240 days of employment in any calendar year

7. In rebuttal Shri Lal Chand Pardesi, Assistant Engineer has stepped in the witness box and has mentioned that petitioners have worked as per Ex. R-1 to Ex. R-8 and has however, admitted that there is no record available with the office show that the petitioners abandoned the job themselves. He maintains that no new recruitment were made after their termination. This the entire evidence.

8. The documents Ex. R-1 to Ex. R-8 show that only two of the petitioners namely Pritam Singh and Ranjit Singh have completed 240 days of work in the calendar years, 1985-86 None of the others have completed mandatory period during their employment with respondent. So, since there is no evidence on record that any notice was served on these two petitioners or that they were offered retrenchment compensation, therefore, their termination cannot be held to be legal and justified especially when abandonment is not proved by the respondent. The only point which requires consideration is that after 1986 no written represnetation was made by either of these petitioners in writing, though according to them, they approached the office and they were assured verbally that they will be provided the employment. Limitation act is not application to the Industrial Disputes Act. Moreover in view of the fact that petitioners have stated on oath that they kept on visiting the office of the respondent, which fact not specifically disputed by the respondent, when shows that they have been raising this issues, So delay alone will not be sufficient to defeat their cause. I, therefore, hold that both these workmon are entitled to be re-instated as their termination is not proper and justified.

9. As regards other petitioners, admitedly they have not completed 240 days of work in any of the calendar years. The petitioners have referred to the Certified Standing Orders, which one applicable to the parties, since 1984. Admittedly, no notice was served on the petitioners under these Certified Standing Orders. A specific allegation has been made in the claim petition in this regard, but no reply has been given to these averments. Respondent has neither mentioned that Certified Standing Orders are not applicable nor has disputed that a 10 days notice was required to be given before terminating their services. So, these allegations have been impliedely admitted by the respondent. The reference which has been received in this Court also speaks of any notice, charge-sheet or enquiry in addition to the non compliance of the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947. Therefore, the fact remains that the notices which was required to be given under the Certified Standing Orders has not been served by the respondent on the petitioners and their termination is violative of the Certified Standing Orders. So, the remaining six petitioners are also entitled to be re-instated.

10. Now coming to the other consequential benefits, the petitioners especially petitioners Pritam Singh and Ranjit Singh have come to the Court at a very belated stage *i. e.* almost after 10/11 years of their alleged termination. Therefore, they are not entitled to the relief of back wages, continuity of service from the date of termination and they are only entitled to the relief of re-instatement from the date of the receipt of the reference in this Court. They are also not entitled to the back wages for similar reasons.

11. Similarly other petitioners have not come to the Court properly and they have been terminated in the years, 1993 to 1995. Therefore, they are also not entitled to the continuity of service from the date of their termination or back wages. Rather they will be re-instated from the date of reeeipt of the reference to this Court. Hence the issue is decided accordingly.

12. *Issues No.* 2&3.—During the course of arguments both these issues have not been pressed by the parties. Hence, both these issues are decided against the respondent.

RELIEF

13 Keeping in view the afereseid discussion,I, hold that the petitioners are entitled to be re-instated in service with continuity and seniority from the date of the receipt of the reference in this Court, but without any back wages. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to the appropriate Government for its publication.

Announced in the Open Court today this 15th day of March, 2002.

Seal. ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge, Himachal Pradesh Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla

Ref. No. 89/2000

Decided on : 16-3-2002

Shri Lekh Ram .. *Petitioner.*

Vs.

Cosmo Ferriets Ltd. Jabli District Solan .. *Respondent.*

Reference Under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947

16-3-2002 : *Present* : Shri J. C. Bhardwaj A. R. for the petitioner

Shri Rahul Mahajan Advocate : for the respondent.

Learned counsel has made statement on oath that the petitioner has settled the dispute with the respondent and the respondent has filed a compromise which is an record and in Ex. PX.

In view of the statement and settlement filed by the respondent, the reference stands answered accordingly. Let a copy of this order be sent to the appropriate Government.

Seal

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal cum Labour Court,
Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presiding Judge Himachal Pradesh Labour Court, Shimla

Ref. No. 40 of 1997

Instituted on : 17-3-1997

Decided on : 22-3-2002

1. Shri Dev Raj s/o Shri Lekh Ram
2. Shri Sarvjit s/o Shri Mansa Ram

Petitioner.

Versus

Chairman, Amar Khadi Gramoudyog Samit, The Mall, Solan, Himachal Pradesh ... *Respondent*

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947

For petitioners : Shri I. C. Bhardwaj, A. R.

For respondent : Shri O. P. Sharma, Advocate.

ORDER

The following reference has been received from the appropriate Government :

> "Whether the termination of Services of S/Shri Dev Raj and Sarbjeet Singh by the Chairman, Amar Khadi Gramoudyog Samiti, The Mall, Solan (H.P.) w.e.f. 31-12-1994 without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 on account of alleged trade union activities is legal and justified, if not, to what relief of past service benefits including back wages, seniority and amount of compensation, the above workers are entitled ?"

2. Joint claim petition has been filed by both the petitioners alleging therein that they were employed as Machine Operators and they worked till 31-12-94 when their services were terminated on account of Trade union activities. It is submitted that Petitioner No. 1 was the Secretary and Petitioner No. 2 was the President of the Amar Khadi Gramoudyog Kramchari Union and the Union had served a demand notice on 20-3-1994. The conciliation proceedings as per that demand notice were taken up by the Labour-*cum*-Conciliation Officer but the matter could not be resolved in conciliation and the reference was sent to this Court reference No. 2 of 1995. It is submitted that the services of the petitioners were terminated during the pendency of the conciliation proceedings & after the demand notice had been served as petitioners did not oblige the respondent by singing settlement favourable to them.

3. It is further contended that the retrenchment notice was served in the petitioners on 31-12-1994, but no retrenchment compensation as was mentioned in that notice was paid to them. It is also submitted that the calculation of the compensation which were made in that notice were incorrect and less amount was offered.

4. It is submitted that respondent did not take the prior approval of the Labour Court, or the Industrial Tribunal or any other competent authority before terminating the services of the petitioners. Therefore, their termination is violative of the Industrial Disputes Act. It is also contended that persons, junior to them were retained, whereas the petitioners being the union leaders were terminated by adopting unfair labour practice. Hence they are entitled to be re-instated *w. e. f.* 31-12-1994 with full back wages and continuity in service.

5. In the reply filed by the respondent, preliminary objections have been raised that the services of the petitioners were terminated due to the bad economic and financial position the respondent and not for the alleged Trade Union activities. It is also submitted that petitioners being the junior most employees were terminated on the basis of first come last go principle after paying them the dues through Bhagat Urban Co-operative Bank Ltd. It is also contended that union was got registered lateron by misrepresenting the facts.

6. on merits, it was contended that the services of the petitioners were terminated after serving them legal notice and paying them the retrenchment compensation which was due to them. It is also submitted that clause C of Section 25-F of the Industrial Disputes Act is not a condition precedent and it is only a requirement for keeping the Government informed about the condition of employment in Industries within its area. It is also contended that no prior a approval of the Government was required. It is also contended that the reference which was sent to this Court on the demand notice was mutually settled by the parties and the Tribunal was informed and so there was no necessity of filing the application under section 33(2) B of the Act. Hence, the claim petition deserves to be dismissed.

7. On the pleadings of the parties my learned predecessor framed the following issues on 19-11-1997:

1. whether the petitioners have been retrenched by the respondent without any notice, chargesheet and enquiry and also in violation section 25-F of the act on the ground as alleged? OPP.
2. Whether the claim of the petitioners is not maintainable on the grounds as alleged in the preliminary objections ? ...OPR
3. Relief.

FINDINGS

8. *Issues* 1 & 2.—The petitioners appeared in the witness box in support of their claim and have maintained that they were not paid the retrenchment notice. It is also contended that junior persons are still being retained. Also that a dem nd had been raised by the union of which they were the office bearers as per Ex. PA and since no settlement could be arrived at the dispute was referred to the labour court *vide* Ex. PB and Ex. PC further that both the petitioners were terminated during the pendency of the conciliation proceedings and reference. Petitioners have also mentioned that they did not receive Ex. PC. The petitioners have denied that they were the junior most employees and they had been sent the money by cheque.

9. In rebuttal, Shri Hem Raj, Manager M/s Amar Khadi Gramaudyog Samiti has appeared. He has reiterated that the services of the petitioners were terminated legally by serving a notice on them and paying them the retrenchment compensation and also that they being the junior most employees were terminated on the basis of last come first go principle. It is submitted that the payments were sent through chaeque. However, in the cross-examination, he has made it clear that he is not aware whether the cheques were infact encashed or not. He has however stated that Deva Nand, Geeta Ram, Madan, Vimla and Rakesh were not working in the same unit, but in the different unit and ha stated that Director and the Chairman of both the units are operate though they belong to the same family. Nothing has been stated regarding seeking the approval of

the authority before whom the proceedings were pending for approval of the action taken of the terminating the services of the petitioner on by the employer.

10. In the light of this evidence, it has to be seen whether the termination of the petitioner in accordance with law or not. It is admitted that demand had been raised by the union *vide* Ex. PA and on the basis of the demand raised by the workers, the matter had been referred to the Court for adjudication as Reference No. 2 of 1995. It is also not disputed that no application was given by the respondent seeking an approval of the retrenchment/termination of the petitioners. The reply that the matter which was raised and referred to the Court was amicably settled between the parties sometime in 1997 is not sufficient to wriggle out of the obligation to seek approval of the authority concerned if an employee is terminated during the pendency of such dispute/proceedings. Section 33-2 (B), which is reproduced below can be quoted for ready reference: -

> "33. Conditions of service, etc., to remain unchaged under certain circumstances during pendency of proceedings.—
>
> (2) During the pendency of any such proceeding in respect of on industrial dispute, the employer may, in accordance with Standing Orders applicable to a workman concerened in such dispute or, where there are no such standing order, in accordvnce with the terms of the contract, whether express or implied, be between him and the workman
>
> (*b*) for any misconduct nor connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, that workman:
>
> Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer.."

11. Hon'ble the Supreme Court has held in its recent judgment reported in 2002 LLR-237 that the application by the employer seeking approval of his action of dismissal/termination of an employee is a mandatory obligation and has to be fulfilled. It has also been held that the order of retrenchment and termination of an employee will in fact become dejure only on the approval by the authority concerned. It is also held that there is no need for moving an application under Section 33-A of the Act for getting an adjudication. Lastly, it has been held that by not moving an application for seeking approval for the action by the employees will amount to not fulfilling the statutory obligation created by law. The observation are reproduced.—

> "The view that when no application is made or the one made is with drawn, there is no order of refusal of such application on merit and as such the order of dismissal or discharge does not become void or inoperative unless such an order is set aside under Section 33 A cannot be accepted. In our view not making an application under section 33(2) (*b*) seeking approval or with drawing an application once made before any order is made thereon, is a clear case of contravention of the proviso to section 33 (2) (*b*). An employer who does not make an application under section 33(2) (*b*) or withdraws the one made, cannot be regarded by relieving him of the statutory obligation created on him to make such an application. It is so done he will be happier or more comfortable than an employ who obeys the command of law and makes an application inviting scrutiny of the authority in the matter of granting approval of the action taken by him. Adherence to an obedience of law should be obvious and necessary in a system governed by rule of law. An employer by design can avoid to made an application after dismissing or discharging and employee or files it and put it befor an order is passed on it, on its merits, to take a position that such order is not inoperative or void till it is set aside under section 33A nothwithstanding the contravention of section 33(2) (*b*) proviso, driving the employee to have recourse to one or more proceeding by making a complaint under section 33A or to raise another industrial dispute or to make a complaint under section 31 (1). Such an approach destroys the protection specifically and expressly given to an employee under the said proviso as against possible victimization, unfair labour practice or harassment because of pendency of industrial dispute so that an employee can be saved from hardship of unemployment

12. In the present case, it is admitted that demand had been served. It was pending consideration and matter had been referred to the Labour Court for adjudication but during the pendency of such proceedings the services of the petitioners were terminated and no application was moved by the employees seeking approval of the action taken by him. Therefore, their termination is illegal and unjustified.

13. Now coming to the plea retrenchment compensation though was offered, but was not received by the petitioners cannot be interpreted in favour of the petitioners. Though in their statements, both the petitioners have mentioned that Ex. PC has not been received by them, but in the reply in Para-3, petitioners have mentioned that the management had sent a retrenchment notice on them as per Annexure PC on 31-12-1994. However, no retrenchment compensation has mentioned therein was paid to them, so irrespective of the that both the petitioners have denied receipt of Ex. PC in this statement in the court let this fact stands admitted in the claim petition itself. Therefore, it is establised that view this Document EX.. PC, petitioners were offered the retrenchment compensation simultanously with the notice of retrenchment. Both of them were directed to receive this amount from the office. It was also offered that in case the matter of increase of wages is decided in favour of the workers, then the remaining amount will be sent to them. Ex. PC is a just compliance of the requirement of law, the retrenchment compensation has been offered to them and the retrenchment compensation has been calculated by them as per the office record. Therefore, the retrenchement of offering the retrenchment compensation has been fulfilled. The notice also mentions that they have been offered one months pay in lieu of the notice period and the retrenchment compensation for 15 days for every completed years of employment. Therefore, on this account, the order of retrenchment cannot be held to be invalid or unjustified

14. Now coming to the question that the petitioners not being the junior most employees, no convincing evidence has been produced by the petitioners. They could have summoned the record from the respondent showing the certain persons were junior to them, but were still retained. However, despite taking this plea which was contested by the respondent no such record was sought from the employer to prove the plea. Therefore, I do not find any substance in the plea. However, since the respondent has failed to comply with the provisions of Section 33 (2) (*b*) of the Act, the termination/retrenchment of the petitioners cannot be held to be justified and they are entitled to re-instatement in service.

15. Now coming to the plea of back wages, petitioners though are entitled to the full back wages for this period but there is not evidence on record to suggest that petitioners were un-employed during this period. Petitioners have only mentioned that they are not employed anywhere now-a-days. Whereas the respondent has given the suggestion to them that they are still working

in some factory. In the peculiar circumstances of the case, it will be proper to award them the wages @ 40% of the wages last drawn by them. However they are entitled to the seniority and continuity of service. The issue is decided accoriingly in favour of the petitioners.

RELIEF

16. Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the petitioners are entitled to be re-instated in service with continuity in service and seniority with back wages to the extent of 40% of the wages last drawn by them. The reference is answered accordingly. Let a copy of this award be sent to appropriate Government for its publication.

Announced in the Open Court today this 22nd day of March, 2002.

Seal.

ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

In the Court of Smt. Aruna Kapoor, Presding Judge, H. P. Labour Court, Shimla

Ref. No. . 72 of 1997

Instituted on : 19-5-1997

Decided on : 27-3-2002

Shri Raj Kumar s/o Shri Krishnu Ram, Village Nerush P. O. Samoh, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. .. *Petitioner.*

Versus

Vikas Bybrids and Electronics Ltd., Village Hariapur P. O. Gurumazra, Tehsil Nalagrah, District Solan, H. P. .. *Respondent.*

Reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947

For petitioner : Shri J. C. Bhardwaj, A. R.

For respondent : Shri Pawan Kaprate, Advocate.

AWARD

The following reference has been received from the appropriate Government:—

"Whether the termination of services of Shri Raj Kumar by the Management of M/s Vhel. Industrial, Village Hariapur, Tehsil Nalagarh, District Solan Himachal Pradesh *w. e. f.* 21-9-1996 without any notice, charge-sheet. equiry and without compliance of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 on completion of 240 days service is legal and justified, if not, to what relief of service benefits including back wages, seniority and amount of compensation, Shri Raj Kumar is entitled ?"

2. The petitioner has alleged in the claim petition that he was employed by which 21-9-1995 and was designated as Trainee, though he had already undergone training from ITI Sundernagar. It is submitted that he was terminated on 21-9-1996 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act. More specifically under Section 25-F and N of the Industrial Disputes Act, 1947 (in short, the 'Act'), though the petition had completed more than 240 days as of work. It is also submitted that no enquiry etc. was held against him. Therefore, petitioner is entitled to re-instatement with all consequential benefits.

3. In the reply filed by the respondent, preliminary objections were raised that petition is not maintainable and the petitioner is estopped from filing the claim petitier in view of his own acts and conducts etc. It is also contended that company had no work to offer to the worker, so the entire staff including the workman and employees were laid off. Hence, the present dispute cannot be raised before this forum.

4. On merits, it is submitted that the petitioner has not filed the appointment letter. Therefore, no detailed reply can be submitted. However, as per the averments of the petitioner, his pleas are self-contradictory and since he has joined the service as per the appointment letter issued to him. So he has made himself liable for all the terms and conditiins given in the letter of appointment. It is also submitted that petitioner does not fall within the perview of workman as he has not completed more than 200 days of employment, so Section 25-F of the act is not applicable. Hence that the claim petition be dismissed.

5. During the pendency of the petition, an application under Section 22 of sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 was also moved by the respondent, which was dismissed by this Court *vide* its order dated 27-12-2001.

6. On the pleading of the parties, my learned predecessor framed the following issues on 28-10-1999:—

1. Whether the termination of the petitioner is illegal in view of Section 35-F of the Industrial Disputes Act, 1947 ? If so, its effects ? . . OPP.
2. Relief

FINDINGS

7. *Issue No.* 1.—The claim of the petitioner is that he was appointed as per written appointment letter, though the terms and conditions of the appointment letter were arbitrary, yet the petitioner joined the service of the respondent as he was need being an unemployed person. Further that though he was appoined as Trainee, but thereafter, he was made Assistant Technician and was allowed enhanced pay. Lastly that he had completed more than 240 days of work from 21-9-1995 5 to 21-9-1996, but his services were terminated without complying with the provisions of Section 25-F of the Act. In support of this contention, he has stepped into the witness box himself and has proceduced the copy of diploma which is Ex P-1 and two of his salary slips. He has also produce one certificate Mark-A. The question which has been put to him in the cross-examination are that he has not produced his appointment letter and that he was only appointed as a casual worker. Further that he worked for less than 200 days in the company.

8. The respondent did not lead any evidence though despite opportunities.

9. The evidence which has come on record does not clearly specify the terms and conditions of the appointment as neitl er the petitioner nor the respondent has produced the appointment letter, which was admitedly in writing, therefore, the statement of the petitioner on oath is the only evidence available in this regard. Accerding to him he was appointmed as Trainee initially and thereafter, made Assistant Technician. Though this fact is not admitted by the respondent, but they have failed to lead any evidence either from the record or by Providing any witness examined to prove that the terms of appointment of the petitioner were such whereby his service could have been terminated on completion of specific period. Moreover, it is also not proved by his respondent by leading any evidence that petitioner has not completed 240 days of work during this period of 21-9-1995 to 21-9-1996. Since the entire record must have been available with the respondent. It was expected of them to produce this record, which has not been done. Moreover, no oral evidence has been led in rebuttal, to rebut the statement of the petitioner on oath since it is not disputed that petitioner was workingwith them from 21-9-1995 to 21-9-1996. I, therefore, hold that in the absence of any record and in view of the

statement of the petitoner, it is establishsed that during this period of one year, petitioner had completed 240 days and was etitled to the compliance of section 25-F of the Act before his services could be terminated. However, since neither any notice nor any compensation has been paid to him, therefore, I hold that his termination is illegal and unjustified.

10. The reference has been relieved in this Court in 1997 wlich means that petitioner has knocked the doors of the authority promptly and without any undue. dealay. I, therefore, hold that he petitioner is entitlted to the seniority and continuity of service. The petitioner is also entitlted of the back wages to the extent of 40 % as petitioner has not mentioned in his statement on oath that he was gainfully employed during this period. Hence, the issue is decided accordingly.

RELIEF

11. *Issue No.*—Keeping in view the aforesaid findings and discussion, I hold that the termination of the petitioner is illegal and unjustified and is entitlted tobe re-instated in job with countinuity and seniority with back wages to the extent of 40%. Reference is answered in affirmative. Let a copy of this order be sent to stage government for its publication.

Announced in the Open Court today this 27th Day of March, 2002.

Seal. ARUNA KAPOOR,
Presiding Judge,
H. P. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Shimla.

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जून, 2002

संख्या विद्युत-छ (5)1/2001.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि मै0, जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटिड, जे0 ए0 हाऊस, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर उक्त कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः उप-मुहाल पुनंग, पानवी, बुरुचा व धारयाशंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में करच्छम बांगतू जल विद्युत परियोजना (1000 मैगावाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त परियोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता [उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक)], निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता [उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक)], निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील निचार

गांव	खसरा नं0	रकबा (हैक्टेयर में)
पूनंग	177	0 04 60
	178	0 01 15
	179	0 04 07
	223	0 01 14
	224	0 01 36
	249	0 00 73
	212	0 00 88
	887/227	0 14 73
	886/227	0 03 75
	135	0 18 38
	213	0 04 02
	226	0 03 06
	234	0 02 32
	253	0 27 03
	895/820	0 00 30
पानवी	485	0 33 12
	460	0 15 50
	476	0 09 12
	477	0 16 15
	487	0 17 60
	488	0 11 15
	492	0 11 41
	508	0 08 54
	465	0 01 84
	507	0 08 74
	501	0 11 48
	569	0 01 73
बुरुचा	328	0 00 24
	329	0 00 46
	323/3	0 00 60
धारयाशंग	28/14	0 18 15
	21/1	0 07 80
	21/2	0 01 00
कुल किस्ता ..	33	2 62 15

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विद्युत)।

भाग-2—वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

DIRECTORATE OF COOPERATION HIMACHAL PRADESH

ORDERS

Shimla-9, the 1st May, 2002

No. 6-17/97-Co-op. (T&M).—In continuation to this office order of even number dated 27-4-2001, the tennure of nominated Board of Directors of the H. P. State Co-operative Wool Procurement Federation Ltd., had expired on 27-4-2002.

Whereas the election to the Board of Directors could not be conducted, therefore, I, T. G. Negi, Registrar Co-operative Societies Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in me under section 35-A of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, do hereby extend the period of nominated Board *w.e.f.* 28-4-2002 as referred above for a period of one month or till the election to the Board are conducted, whichever is earlier.

T. G. NEGI,
Registrar Co-operative Societies
Himaceal Pradesh.

Shimla-9, the 21st May, 2002

No. 6-60/96 Coop. (T&M)-I.—In pursuance of Rule 39(1-A) of the H.P. Co-operative Societies Rules, 1971, I, S.K.B.S. Negi, Registrar, Co-operative Societies, H.P. do hereby nominate the following members as

members on the Board of Directors of the H.P. Milkfed Shimla with immediate effect.

1. Shri Fateh Singh. (S.C.)
Village Panjrole,
P.O. Mamligh, Tehsil Kandaghat.
Distt. Solan.

2. Smt. Gian Devi. (S.T.)
V.P.O. Tapri,
Distt. Kinnaur

3. Smt. Sarla Dogra. (Lady Nominee)
V.P.O. Guwardu,
Tehsil and Distt. Hamirpur.

S. K. B. S. Negi.
Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh.

PLANNING DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 11th April, 2002

No. PLG-FC(F) 1-1/98. Estt.—In pursuance of H. P. Government Planning Department Letter No. PLG B (1) 3/97 dated the 2nd April, 2002, one post of Environmental Engineer alongwith incumbent i.e. Shri Tarun Raj Gupta and one post of Statistical Assistant are hereby transferred to Himachal Pradesh State Council of Science, Technology and Environment, Kasumpti, Shimla-9 from Indo Norwegian Project Secretariat of Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla-2 with immediate effect.

2. Shri Tarun Raj Gupta, Environmental Engineer is hereby relieved from his duties *w. e. f.* 11-4-2002 (A. N.) and further directed to report to Member *Secretary, State Council of Science Technology and Environment* for further duties.

Sd/-
Principal Advisor (Planning).

Office of the Controller, Legal Metrology, (Weights & Measures) Himachal Pradesh

ORDER

Shimla-9, the 22nd May, 2002

No. 1-2/70-DFS (W&M)-II/1884-1921.—In partial modification of this office order of even No. 1740-74, dated 13-5-2002, I, R. K. Rakesh, Controller, Legal Metrology (W&M), H.P. in exercise of powers vested in me *vide* section 5(3) of the Standards of Weights & Measures (Enforcement) Act, 1985 (54 of 1985) redefine the limit of Karsog sub-division of Mandi district as a part of Sunder Nagar circle. As such, henceforth, Sh. Ramesh Kumar, Inspector, (W&M), Sunder Nagar and Sh. Jia Lal, Assistant Controller, Legal Metrology (W&M), Mandi will exercise jurisdiction on the said sub-division instead of both Inspector (W&M) Shimla circle and Assistant Controller, Legal Metrology (W&M), Shimla division with immediate effect.

R. K.RAKESH,
Controller, Legal Metrology, (Weights and Measures).

Office of the District Election Officer (Panchayat)-*cum*-Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala (H.P.)

ORDER

Dharamshala, the 14th May, 2002

No. Panch-Kgr/Election (36) 1/2001-219-59.—In exercise of the powers vested in me under section 189 (2) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 30 of Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) rule, 1994 I, Prabodh Saxena, IAS, District Election Officer (Panchayat)-*cum*-Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala, do hereby appoint the following officers as authorised officer for the conduct of Bye-Election for Panchayats in the jurisdiction mentioned against their names below:—

Sl. No.	Name/Designation of Officer	Jurisdiction
1.	B.D.O., Nagrota Surian	G.P. Harsar W. No. 7
	-do-	-do- W. No. 4
	-do-	G.P. Dol W. No. 2
	-do-	G.P. Dol W. No. 6
2.	B.D.O., Pragpur	G.P. Nichla Balwal W.No. 2
	-do-	G.P. Jandour
	-do-	G.P. Kolapur W.No. 7
	-do-	G.P. Nangal-Chowk
	-do-	G.P. Maniala
3	B.D.O., Kangra	G.P. Thana Khas W No. 2.
	-do-	G.P. Chakban-Gheen 2
	-do-	G.P. Abdulapur
4.	B.D.O., Sullah	G.P. Balota.
	-do-	G.P. Ghenchri W. No. 5.
5.	B.D.O., Panchrukhi	G.P. Bhullana W. No. 4.
6.	B.D.O., Lambagaon	G. P. Dagoh
	-do-	G.P. Molag W. No 2
	-do-	G P. Molag
	-do-	G.P. Jagrup Nagar 5
7.	B.D.O., Nurpur	G.P. Lahru W.No 1
	-do-	G.P. Dhaneti Garla 4
	-do-	G.P. Suliali W. No. 11
8.	B.D.O., Fatehpur	G.P. Menoh-Sihal W. No. 7.
	-do-	G.P Machhot W. No 5
9.	B.D.O., Dehra	G.p. Ghallour W. No.2
10.	B.D.O , Rait	G.P. Baslehar W. No.2
	-do-	G.P. Ansui W. No. 4

Seal.

Sd/-
District Election Officer, (Panchayat)-cum-Deputy Commissioner, Kangra at Dharamshala (H.P.).

Office of the General Manager, District Industries Centre, Nahan, Himachal Pradesh

OFFICE ORDER

Nahan, the 24th May, 2002

No. Ind/N/D/Regn-Nova Appliance/84-3278.—Whereas the Industrial Unit under the name and style of M/s Nova Appliances, 46, I. A. Poanta Sahib (H.P.) District Sirmaur, H.P. (hereinafter referred to as the unit) is registered with the Department of Industries on Permanent Basis *vide* No. 6/10/1998/Pmissi dated 5-12-1984 for the manufacturing of Nutan Stoves (Wicks) *w.e f.* 1-10-1984.

And whereas the Unit has closed down and have ceased functioning as per report of the Manager IA. Poanta Sahib, District Sirmaur (H.P).

And whereas the Unit was served with a show Cause Notice *vide* No. Ind/N/D/Regn/ Nova/84, dated

26-4-2002 asking the reason as to why the Unit should not be de-registered for its being closed and not in production to which no reply has been received even after the stipulated period.

Now, therefore, the unit registered under the name and style of M/s Nova Appliances Plot No. 46 I.A. Paonta Sahib is de-registered with immediate effect and Unit shall not be entitled to any assistance to which Small Scale Industrial Units are eligible.

These orders are without prejudice to any action which may follow subsequently against the Unit for recall of Finances/Incentives from the Promoters/Proprietors/Partners of the unit and also for Utilisation or otherwise of any other facility by the Unit.

Sd/-
General Manager,
District Industries Centre,
Nahan, District Sirmaur (H.P.)

भाग-3--अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, बैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेंशयल कमिश्नर तथा कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 6 अप्रैल, 2002

संख्या पब-ए (3) 36/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब-बी (24) 3/89, तारीख 31-7-1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सम्पादक वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सम्पादक वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सम्पादक वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995, के संक्षिप्त नाम में जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है शब्द, चिन्ह और रोमन अंक "वर्ग-II" के स्थान पर "वर्ग-I" शब्द, चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. उपाबन्ध-I का संशोधन.—उक्त नियमों के उपाबन्ध "I" में:—

(क) स्तम्भ संख्या 3 में, शब्द, चिन्ह और रोमन अंक "वर्ग-II" के स्थान पर "वर्ग-I" शब्द, चिन्ह और रोमन अंक (प्रतिस्थापित) किए जाएंगे ।

(ख) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"किसी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए" ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of this department notification No. Pub. A(3) 36/99, dated 6-4-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 2002

No. Pub. A (3) 36/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Information and Public Relations, Editor, (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995, notified *vide* this Department Notification No. Pub. B (24) 3/89, dated 31-7-95 namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information and Public Relations, Editor (Class-I, Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of short title.*—In the short title of the Himachal Pradesh, Department, Information and Public Relations, Editor, Class-I of (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules) for the word, sign and Roman figure, Class-II the word, sign and Roman figure 'Class-I' shall be substituted.

3. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure 'A' to the said rules:—

(*a*) In column No. 3 for the word, sign and Roman ffigure 'Class-II' the word, sign and Roman figure 'Clacs-I' shall be substituted.

(*b*) For the existing entries against Column No. 14, the following shall be substituted, namely:—

"A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India".

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अप्रैल, 2002

संख्या इण्ड-ए0 (ए0) 3-1/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29-8-2001 द्वारा अधिसूचित उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के उपाबन्ध "क" के स्तम्भ संख्या 10 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता"।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. Ind. A (A) 3-1/94, dated 8-4-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th April, 2002

No. Ind. A (A) 3-1/94.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Industries Department Manager/Project Manager, DIC (Class-II, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified *vide* this Department Notification of even number dated 29-8-2001, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Industries Department, Manager/Project Manager, DIC Class-II, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-"A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Industries Department, Manager/Project Manager, DIC Class-II, (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 for the existing title of Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:—

"Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various, methods."

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-1, 16 मई, 2002

संख्या 11-2/93 (लैब) आई0 डी0 भाग-सोलन.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Amar Chand s/o Shri Jai Ram and 8 other workmen (As per Annexure-A overleaf) through Shri J. C. Bhardwaj, Gen. Secy., H. P. AITUC Head Quarter, Saproon, Solan, H. P and The Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division Saproon, District Solan के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Shri Amar Chand, Beldar and 8 other Beldars (As per Annexure-A overleaf) by the Executive Engineer, HPSEB Electrical Division, Solan *w.e.f.* 26-8-1998 on completion of more than 240 days continuous service without giving any notice or notice pay and retaining the juniors in service is proper and justified? If not, what relief in service benefits including seniority and backwages the above workmen are entitiled to ?"

शिमला-1, 16 मई, 2002

संख्या 11-5/99 (लैब) आई0 डी0-भाग-चम्बा.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री भरथु राम सुपुत्र श्री माना, गांव व डाकखाना डण्डी, तहसील सलूनी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश तथा अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल, सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"क्या श्री भरथु राम सुपुत्र श्री माना, गांव व डाकखाना डण्डी, तहसील सलूनी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को दिनांक 31-12-1996 को 10 वर्ष पूर्ण करने पर अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मण्डल, सलूणी द्वारा दिनांक 1-1-1997 से वर्कचार्ज/नियमित न करना उचित है अथवा अनुचित ? यदि अनुचित है, तो श्री भरथु राम किस राहत व क्षतिपूर्ति का हकदार है ?"

"क्या श्री भरथु राम सुपुत्र श्री माना, गांव व डाकखाना डण्डी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल, सलूणी द्वारा दिनांक 1-12-1998 को सेवानिवृत करने के पश्चात् सेवा मुआवजा तथा उपदान का भुगतान न करना उचित व न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कामगार किस वित्तीय लाभ का हकदार है ?"

शिमला-1, 16 मई, 2002

संख्या 11-6/85 (लैब0) आई0 डी0-भाग-शिमला.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rajinder Singh s/o Shri

Jeet Ram, Vilage Majhar, P. O Satlai, Tehsil and District Shimla and the Executive Engineer, I and PH Department Kasumpti Division No. 1, Shimla-9, Himachal Pradesh के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"कि क्या श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री जीत राम, दैनिक भोगी कामगार को अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, कसुम्पटी, मण्डल नं0 1, शिमला-9 द्वारा मौखिक आदेश देकर बिना किसी नोटिस के माह जून, 1999 से नौकरी से निकाला जाना उचित एवं न्याय संगत है? अगर नहीं, तो श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री जीत राम कामगार किस वरिष्ठता, सेवा लाभ एवं राहत का पात्र है?"

"कि क्या अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग मण्डल नं0 1 के द्वारा यह कहना कि श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री जीत राम कामगार द्वारा स्वयं नौकरी छोड़ी गई है समझा जाना उचित है?"

शिमला-1, 17 मई, 2002

संख्या 11-6/85 (लैब0) आई0 डी0-भाग-शिमला.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री ध्यान सिंह सुपुत्र स्व0 श्री पन्ना लाल द्वारा महासचिव, हिम शक्ति परिवहन निगम कर्मचारी संघ 92/2, डिंग मन्दिर रोड़ नजदीक मिल्ट्री गेट, संजौली, शिमला-6 तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0 प्र0 पथ परिवहन निगम, तारा देवी, शिमला, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"कि क्या श्री ध्यान सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री पन्ना लाल, कन्डक्टर को प्रबन्धक निदेशक, हि0 प्र0 पथ परिवहन निगम, शिमला एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0 प्र0 पथ परिवहन निगम, तारा देवी, शिमला के कार्यालय आदेश दिनांक 18-3-1993 द्वारा नौकरी से निकाला जाना उचित एवं न्याय संगत है? अगर नहीं, तो श्री ध्यान सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री पन्ना लाल, कन्डक्टर किस सेवा लाभ एवं राहत का पात्र है?"

शिमला-1, 17 मई, 2002

संख्या 11-5/99 (लैब) आई0 डी0-भाग-चम्बा.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री कर्म चन्द सुपुत्र श्री चमारु राम, गांव चटलूणी, डाकखाना ब्लेरा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा तथा अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"कि क्या श्री कर्म चन्द कामगार सुपुत्र श्री चमारु राम, गांव चटलूणी, डाकखाना ब्लेरा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा को अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियोजक पक्ष के आदेश दिनांक 3-3-1995 द्वारा पाईप फिटर के पद पर नियमित/वर्क चार्ज नहीं करके सहायक पाईप फिटर के पद पर वर्कचार्ज करने की कार्यवाही उचित व न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उपरोक्त कामगार उपरोक्त नियोजक पक्ष से किस पूर्व वेतन, वरिष्ठता, पूर्व सेवा लाभों और राहत का पात्र है?

शिमला-1, 17 मई, 2002

संख्या 11-2/86 (लैब) आई0 डी0 भाग-Bilaspur.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Daya Ram s/o Shri Rup Lal, Village Barsand, P.O. Gherwin, Distt. Bilaspur and the Executive Engineer, I & PH Division Ghumarwin, Distt. Bilaspur H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त को गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Daya Ram, Worker (Beldar) by the Executive Engineer, I & PH Division, Ghumarwin, District Bilaspur, H. P. *w. e. f.* 1-9-1995 is legal and justified? If not, to what relief the worker Shri Daya Ram is entitled to?"

शिमला-1, 17 मई, 2002

संख्या 11-2/86 (लैब0) आई0 डी0 भाग-Bilaspur.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rajesh Kumar

through Sh. Sundar Singh Sippy, Q. No 100/3, Roda Sector-2, Bilarpur, District Bilaspur, H. P. and (I) Chairman-*cum*-Managing Director, H. P. Ex-Servicemen Corporation, Hamirpur (II) Manager, H. P. Ex-Servicemen Corporation, P. O. Barmana, District Bilaspur, H. P. के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Rajesh Kumar, clerk by the Management of (I) Chairman-*cum*-Managing Director, H. P. Ex-servicemen Corporation, Hamirpur, H. P. (II) Manager, H. P. Ex-serviceman Corporation, P. O. Barmana, Distt, Bilaspur *w. e. f.* 31-5-2000 without giving him reasonable and adequate apportunity of being heard in violation of principles of fairplay and natural justice is legal and justified ? If not, what relief of past service benefits including backwages, seniority and amount of comensation Shri Rajesh Kumar is entitled to ?"

शिमला-1, 21 मई, 2002

संख्या 11-1/86 (लैब0) आई0 डी0-भाग-Paonta Sahib-I.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ashok Kumar Sharma s/o Shri Vidhya Sagar Sharma, c/o Ms. Poonam Sharma, Draughtsman Electrical Division, H. P. S. E. B., Gondpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Divisional Manager, Himachal Pradesh State Forest Corporation Ltd. Him-Kashth Sale Depot, Mantaruwala, Paonta Sahib, District Sirmaur (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of the services of Shri Ashok Kumar Sharma s/o Shri Vidhya Sagar Sharma by the Divisional Manager, Himachal Pradesh State Forest Corporation Ltd. Him-Kashth Sale Depot, Mantaruwala (Paonta Sahib), District Sirmaur, H. P. *w. e. f.* 20-9-88, without complying the section 25-F/25-N of the Industrial Dispute Act, 1947 is legal and justified ? If not, what relief of service benefits including backwages, seniority and amount of compensation Shri Ashok Kumar is entitled to ?"

शिमला-1, 21 मई, 2002

संख्या 11-1/86 (लैब0) आई0 डी0 भाग-पौंटा साहिब.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्री लायक राम सुपुत्र श्री राम किशन, गांव बाकुंआ, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश तथा अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, मण्डल, पांवटा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"कि क्या श्री लायक राम सुपुत्र श्री राम किशन, गांव बाकुंआ, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 को बतौर दैनिक भोगी बेलदार 240 दिनों से अधिक की सेवाएं करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड मण्डल, पांवटा, जिला सिरमौर द्वारा उक्त श्रमिक की सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना समाप्त करना उचित एवं न्याय संगत है ? यदि नहीं, तो उक्त श्रमिक किन सेवा लाभों व क्षतिपूर्ति का पात्र है ?"

शिमला-1, 21 मई, 2002

संख्या 11-6/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-Shimla.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Roop Dass s/o Shri Hazaru Ram, r/o Village and P. O. Kadarghat, Tehsil Suni, District Shimla and the Executive Engineer, H. P. S. E. B. Division, Suni, District Shimla, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"कि क्या श्री रूप दास सुपुत्र श्री हजारू राम कामगार का उप-मण्डल अधिकारी, हि0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद, उप-मण्डल, सुन्नी, जिला शिमला द्वारा समयबद्ध कार्य की समाप्ति पर दिनांक 25-9-1993 के पश्चात् नौकरी से बिना किसी नोटिस के निकाला जाना उचित एवं न्याय संगत है ? अगर नहीं, तो श्री रूप दास सुपुत्र श्री हजारू राम कामगार किस पेंशन, वरिष्ठता, सेवा लाभ एवं राहत का पात्र है ?"

शिमला-1, 21 मई, 2002

संख्या 11-6/85 (लैब0) आई0 डी0 भाग-Shimla. —अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hitender Singh s/o Shri Durga Singh, Anand Kuteer, Dhalli, Shimla-12 and Chairman, Canteen Managing Committee, Army Training Command, Shimla-3 (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Hitender Singh Rathor (Clerk-*cum*-Auditor) s/o Shri Durga Singh by the Deputy Chairman, Head-Quartar ARTRAC Canteen, Shimla-3 *w. e. f.* 17-12-97 after serving one month notice and then employing the junior workmen is proper and justified ? If not, what relief of service benefits including salary, seniority and compensation the above workman is entitled to ?"

शिमला-1, 21 मई, 2002

संख्या 11-2/93 (लैब0) आई0 डी0 भाग-सोलन.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि श्रीमती नर्वदा देवी, कामगार पत्नी श्री सुरेश कुमार तथा प्रबन्धक, शर्मा इन्डस्ट्रीज, शैड नं0-1, चम्बाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"क्या श्रीमती नर्वदा देवी, कामगार को प्रबन्धक, मै0 शर्मा इन्डस्ट्रीज, शैड नं0-1, चम्बाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा 11-04-2000 से बिना किसी पूर्व सूचना व नोटिस तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ की अनुपालना किए बिना नौकरी से निकाला जाना उचित एवं न्याय संगत है ? यदि नहीं, तो कामगार श्रीमती नर्वदा देवी किस क्षतिपूर्ति एवं सेवा लाभों की पात्र है ?"

हस्ताक्षरित/-
श्रमायुक्त ।

विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2002

संख्या एम0पी0पी0-बी(2) 60/84-पार्ट-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में तकनीकी सहायक (अराजपत्रित वर्ग-III) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय, तकनीकी सहायक (अराजपत्रित वर्ग-III) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां. —(1) बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग की अधिसूचना संख्या एम0पी0पी0-बी(2)60/84, दिनांक 31-7-1991 द्वारा अधिसूचित विद्युत निरीक्षणालय विभाग में तकनीकी सहायक (वर्ग-III) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1986/1991 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है कि ये विद्युत निरीक्षक के पद को लागू हों ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या नियुक्ति या कार्रवाई विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

उपाबन्ध-"अ"

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग हिमाचल प्रदेश में विद्युत तकनीकी सहायक (अराजपत्रित वर्ग-III) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	तकनीकी सहायक
2.	पदों की संख्या	10 (दस)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	रुपये 5800-200-7000-220-8100-275-9200.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन पद
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा ।	लागू नहीं : परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या सविदा पर नियुक्त किए गए पहले से ही सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

	परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दिया जायेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी कि सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिये आयु की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें की पद (पदों) को यथास्थिति आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता हो या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता हो । (2) अन्यथा सुभ्रर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव अपेक्षा के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हतायें ।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ?	लागू नहीं
9. परिवीक्षा यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	75 प्रतिशत सैकेन्डमेन्ट आधार पर तथा 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमेन्ट द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनमे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद /हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में इस पद के समरूप वेतनमान पर कार्यरत और विद्युत इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अर्हित बिजली मिस्त्री में से प्रोन्नति द्वारा जिनकी श्रेणी में कम से कम नियमित या तदर्थ (31-3-1998) तक सहित नियमित सेवा दस वर्ष हो । ऐसा न होने पर हि0 प्र0, राज्य विद्युत परिषद /हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग में इस पद के समरूप वेतनमान पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से 'सैकेन्डमेंट' द्वारा । नोट : (1) प्रोन्नति के सभी मामलो में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सभरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमो में यथाविहित सेवाकाल के लिये निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, बशर्ते कि संमीर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर की गई हो : (क) उस सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, नियमित सेवा/नियुक्ति सहित i. e. followed by regular service / appointment को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी, हो : परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी

प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, बशर्ते कि सम्बन्धित पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर की गई हो :

परन्तु 31-3-1998 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित हो।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	लागू नहीं।
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

[Authoritative English text of this department notification No. MPP-B(2)60/84, dated 29th January, 2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

MPP AND POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th January, 2002

No. MPP-B(2)-60/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant, Class-III (Non Gazetted), in the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh as per Annexure-"A", attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Electrical Inspectorate, 2002.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Savings.*—(1) The Himachal Pradesh Electrical Inspectorate Department Class-III services (Technical) Recruitment and Promotion and certain conditions of services Rules, 1986 notified *vide* MPP & Power department notification No. MPP-B(2)-60/84, dated 31-7-1991, are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Technical Assistant (Class-III—Non-Gazetted).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub Rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF M. P. P. AND POWER HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Technical Assistant
2. Number of posts	10 (Ten)
3. Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 5800-200-7000-220-8100-275-9200.
5. Whether selection post or non-selection post.	Non-selection
6. Age for direct recruitment.	N. A. : Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis : Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc*

	basis had become over age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment : Provided further that age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who were/are finally absorved in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies. *Note.*—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.	
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not Applicable	
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Not Applicable	
9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.	
10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.		75% on secondment basis and 25% by promotion failing which by on secondment basis.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.		By promotion from amongst Electrician who are I.T.I. qualified and possess at least 10 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998), service in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of the post of Junior Engineers (Elect.) working in the identical pay scale of this post from H.P. State Electy. Board/H.P. Public Works Department. *Note* (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service, as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptabe process of selection in accordance with the provisions of R. & P. Rules, provided that:— In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998) followed by regular service/ appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior

to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh, Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the *ad hoc* appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R & P Rules :

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

Note.—2. Provisions of columns 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under column 2 are increased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14. Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Not applicable
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 मई, 2002

संख्या मुद्रण (बी) 2-17/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, में अक्षर वितरक, वर्ग-III (अराजपत्रित) अनिपिक वर्गीय सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अक्षर वितरक, वर्ग-III (अराजपत्रित) अनिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 73-15/50, तारीख 21-6-1963 द्वारा अधिसूचित "दी हिमाचल प्रदेश प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमैंट क्लास-III एण्ड क्लास-IV (मिनिस्ट्रीयल, टैक्नीकल एण्ड नान टैक्नीकल सर्विसिज) रैक्रूटमैंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कण्डीशन आफ सर्विस रूल्ज, 1963" का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये अक्षर वितरक के पद को लागू हों ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अक्षर वितरक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	अक्षर वितरक
2. पदों की संख्या	6 (छः)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) अनिपिकीय वर्गीय सेवाएं ।
4. वेतनमान	रुपये 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
5. चयन पद अथवा अचयन पद ।	अचयन पद

6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु ।	18 से 45 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप मे आमेलित किए गये हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद/पदों को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है । (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	(क) अनिवार्य अर्हतायें : (*i*) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक/हायर सकैण्डरी पार्ट-I या इसके समतुल्य । (*ii*) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पोजिंग ट्रेड में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय ट्रेड/शिक्षुता प्रमाण-पत्र या इसके समतुल्य । (*iii*) विभिन्न प्रकार व आकार के टाईप्स को पहचानने की तथा टूटे हुए कम्पोजड मैटरज को वितरित करने की योग्यता रखता हो (पद के लिए चयन व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर होगा) । (ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ?	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक अर्हतायें : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% प्रोन्नति द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा ।	फर्मे वाशरों में से, जिनकी 5 वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड में (31-3-1998 तक की गई) लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को मिलाकर संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर फर्मे कैरियर तथा प्रेस मजदूरों में से, जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-1998 तक की गई) लगातार तदर्थ सेवा को मिलाकर संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा : परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र फर्मे कैरियर और प्रेस मजदूरों की उनकी सेवाकाल के आधार पर, पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक वरिष्ठता सूचि तैयार की जाएगी : परन्तु यह और भी कि पद के लिए चयन व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर होगा ।

	अक्षर वितरक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दो सूचीय रोस्टर अपनाया जाएगा :—	
	प्रथम पद : प्रोन्नति द्वारा द्वितीय पद : सीधी भर्ती द्वारा (तदोपरान्त रोस्टर की पुनरावृति होगी) ।	
	(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवा-काल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिसमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :	लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में जिसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।	
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।	
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।	
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि, यथा-स्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, जिसका पाठ्यक्रम, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।	
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।	
स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता	17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं
	18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन, नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English text of this department notification No. Mudran (B) 2-17/99, dated 21-5-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st May, 2002

No. Mudran (B) 2-17/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with H. P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Distributor, (Class-III Non-Gazetted) Non-Ministerial Services in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Distributor (Class-III Non-Gazetted) Non-Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2002.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(*i*) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Class-III and Class-IV (Ministerial, Technical and Non-Technical) Service (Recruitment, Promotion and Certain Conditions of Service) Rules, 1963 notified *vide* this Department notification No. P. 73-15/50, dated 21-6-1963 are hereby repealed to the extent these rules are applicable to the post of Distributor

(*ii*) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under sub-rule (*i*) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Principal Secretary (Ptg. & Sty.).

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DISTRIBUTOR (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Distributor
2.	Number of posts	6 (Six)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services.
4.	Scale of pay	Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
5.	Whether selection post or non-selection post.	Non-selection
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 and 45 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential Qualifications :* (*i*) Matric/Higher Secondary Part-I or its equivalent from a recognised University/Board. (*ii*) National Trade Apprenticeship Certificate Course of atleast two years duration in the trade of Composing or its equivalent from an I.T.I. duly recognised by the State Technical Education Board or from an Institute duly recognised by the Central/H. P. Government. (*iii*) Should be able to distinguish between types of different kinds and sizes and distribute brokenup composed matter.

		Selection to the post shall be made on the basis of practical test. *Desirable Qualifications*: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?	*Age* : Not applicable *Educational Qualifications*: Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.	(*i*) 50% by direct recruitment; and (*ii*) 50% by promotion.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Forme Washers who possess five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Forme Corriers and Press Mazdoors who possess seven years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the grade: Provided that for the purpose of promotion a combined seniorits list in respect of eligible Forme Carriers and Press Mazdoors based on the length of service from their date(s) of appointment (s) as such without disturbing their unitwise *inter-se* seniority shall be prepared: Provided furteer that the selection to the post shall be made on the basis of practical test. For filling up the posts of Distributor, the following to points roster shall be followed :— 1st post : By promotion 2nd post : By direct recruitment. (Thereafter the roster shall repeat itself). (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that :— (*i*) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998 followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, which ever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. *Explanation*.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services)

		Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder. (2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules : Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998, as referred to above shall remain unchanged.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination.	Not applicable
18.	Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the H. P. P. S. C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2002

संख्या मुद्रण (बी) 2-1/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या मुद्रण (बी) 2-1/99, तारीख 25-9-2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध "क" में :—

(क) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"लिपिकों/कनिष्ठ सहायकों के सामान्य लिपिकीय काडर में से, जिनका 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 10 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो । प्रोन्नति द्वारा, परन्तु यह कि उन लिपिकों को, जो वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नत हुये हैं या करुणामूलक आधार पर नियुक्त हुए हैं, ऐसी प्रोन्नति/नियुक्ति के समय जिनकी शैक्षणीक अर्हताएं मैट्रिक पास या केवल मैट्रिक अंग्रेजी सहित, हिन्दी रत्न पास हो, तब तक, वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत नहीं किए जायेंगा, जब तक कि वे सीधी भर्ती के लिए यथाविहित, अनिवार्य अर्हतायें अर्थात् मैट्रिक द्वितीय श्रेणी में या 10 जमा 2 की परीक्षा पास नहीं कर लेते ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव मुद्रण एवं लेखन ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Mudran (B) 2-1/99, dated 24-5-2002 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th May, 2002

No. Mudran (B) 2-1/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Assistant (Class-III Non Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified *vide* this Deprtment Notification No. Mudran (B)2-1/99, dated 25-9-2000, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Assistant (Class-III

Non-Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2002.

(ii) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Senior Assistant, (Class-III Non Gazetted) ministerial services, Recruitment and Promotion Rules, 2000:—

(*a*) For existing main provisions against Col. No. 11 the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst the common Clerical Cadre of Clerks/Junior Assistants with 10 years regula. service or regular coubined with continuos *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service in the grade.

Provided that those Clerks who have been promoted from amongst the Class-IV employees or appointed on compassionate grounds having the educational qualification Matric pass or Matric in English only and Hindi Rattan pass at the time of such promotion/appointment shall not be promoted to the post of Senior Assistant unless they possess the essential qualification *viz.* Matric 2nd Division or 10+2 pass as prescribed for direct recruitment".

By order,

Sd/-
Principal Secretary,

भाग-4—स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

-शून्य-

भाग-5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

ब अदालत जनाब सब-रजिस्ट्रार घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

श्री मस्त राम, सुख राम, पुत्रान श्री महन्त राम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बम्ब, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ..वादी।

बनाम

1. ग्राम जनता, 2. नीलमा देवी पुत्री सरला देवी 3. टेक चन्द पुत्र सरला देवी, 4. पूनम कुमारी, 5. कान्ता देवी पुत्रियां सरला देवी पत्नी श्री चुनी लाल जाति ब्राहमण, निवासी गांव लुणाधा इलाका सुरांगा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

प्रतिवादीगण ।

दरख्वास्त अन्डर सैक्शन 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेसन एक्ट

हरगाह उपरोक्त फरीक दोयमों व ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण गस्त राम, व सुख राम ने दरख्वास्त अन्डर सैक्शन 40, 41 बावत रजिस्ट्रड किये जाने वसीयत नामा मृतका सरला देवी पुत्री श्री मनसा राम जाति ब्राहमण निवासी गांव बम्ब परगना अजमेरपुर तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश व पत्नी श्री चुनी लाल गांव लुणाधा इलाका सुरांगा तहसील, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश तारीख 6-5-2001 बावत जायदाद गांव बम्ब, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दायय कर रखी है। अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त वसीयत नामा पर किसी किस्म का कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 18-6-2002 को सुबह 10.00 बजे इस कार्यालय मे हाजिर हो कर पश करें। अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार घुमारवीं,
जिला बिलासपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री चन्दू राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री तुलसी राम पुत्र श्री सुन्दर लाल उर्फ सुन्दर सिह, गांव णकरोहा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तंगत नाम दरुस्त करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी ने इस अदालत मे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम सुन्दर लाल है, जब कि पंचायत रिकार्ड में सुन्दर सिह लिखा गया है। इसे पंचायत रिकार्ड में ठीक किया जाए ।

अत: आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश करें, अन्यथा नाम दरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 18-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । चन्दू राम शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री सन्तोष कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री मान्तरू राम सुपुत्र श्री गंगा राम, गांव कढ़ोह, परगना बसेह, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—दरख्वास्त अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री मान्तरू राम सुपुत्र श्री गंगा राम, गांव कढ़ोह, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की का जन्म दिनांक 7-9-1996 को हुआ है परन्तु बच्चे को जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुलज्यार के अभिलेख में दर्ज न है । अत: श्री मान्तरू राम अपनी लड़की प्रमिला की जन्म तिथि 7-9-1996 को ग्राम पंचायत कुलज्यार में दर्ज करवाना चाहता है ।

अत: इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुलज्यार के अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 17-6-2002 को या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर होकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 10-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । सन्तोष कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, झण्डूता,
जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

अ अदालत श्री सन्तोष कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, झण्डूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री सूंका राम, गांव डोल लसावा, परगना सुनहाणी, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) ।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—दरख्वास्त अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री सूंका राम, गांव डोल लसावा, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की का जन्म दिनांक 15-7-1996 को हुआ है परन्तु बच्चे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोह के अभिलेख में दर्ज न है । अतः रमेश चन्द अपनी लड़की नीलम कुमारी की जन्म तिथि 15-7-1996 को ग्राम पंचायत बलोह में दर्ज करवाना चाहता है ।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बच्चे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोह के अभिलेख में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 18-6-2002 को या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर होकर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 17-4-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । सन्तोष कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, झण्डूता,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०) ।

अ अदालत श्री हरबन्स लाल इन्दौरिया सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दीना नाथ बनाम गोविन्द

श्री दीना नाथ शंकर वासी हरी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०) वादीगण ।

बनाम

श्री गोविन्द पुत्र गोलक, वासी ककड़, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) । प्रतिवादीगण ।

दरख्वास्त दस्ती इन्द्राज खसरा न० 852 रकबा तादादी 0-8 मरले वाक्या टीका ककड़, तप्पा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त विषय में प्रतिवादी को कई बार समन जारी किये गये अमर रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अनुसार उनकी तामील असालतन न हो रही है । वे जानबूझ कर अदालत में आने से टालमटोल कर रहे हैं । इसलिए इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनकी तामील साधारण ढंग से करवाया जाना कठिन है ।

अतः उपरोक्त प्रतिवादी को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बजाए पैरवी मुकदमा असालतन या वकालतन दिनांक 18-6-2002 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत आवें । अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 16-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हरबन्स लाल इन्दौरिया,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भोरंज, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

अ अदालत श्री हरबंस लाल इन्दौरिया, सब-रजिस्ट्रार भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

अशोक कुमार बनाम आम जनता

विषय - दरख्वास्त बाबत रजिस्टर करवाने तकसीम नामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1903.

1. श्री अशोक कुमार, 2. सुभाष चन्द पिसरान इन्दरजीत सिंह, वासी धलेड़ा, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी ।

उपरोक्त उनवानवाला में आर्थी अशोक कुमार आदि पुत्र इन्द्रजीत, वासी धलेड़ा ने दिनांक 13-3-2002 को एक दरख्वास्त गुजारी है कि इन्द्रजीतपुत्र लाल सिंह दिनांक 3-2-2002 को स्वर्ग सिधार चुका है । व इन्द्रजीत ने दिनांक 27-1-2002 को अपने जीते जी अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत नामा अपने दो पुत्रों के नाम सर्वश्री अशोक कुमार व सुभाष चन्द के नाम तहरीर करवा रखी है जो बिना पंजीकृत है । जिसे अब पंजीकृत करवाना चाहता है ।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को इस वसीयत के पंजीकृत के बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत हो कर एतराज पेश कर सकते है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाइ जा कर वसीयत पंजीकृत कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 16-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । हरबन्स लाल इन्दौरिया,
सब-जिस्ट्रार,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।

H M G F HIRE PURCHASE PVT LTD.

Regd. Office
Ward No. 8, Gandhi Nngar, Hamirpur-177001, Himachal Pradesh

FORM 155
(*See Rule* 329)

THE COMPANIES ACT, 1956
MEMBERS VOLUNTARY WINDING UP

NAME OF COMPANY :

H. M. G. F. HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION NOTICE CONVENING FINAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuance to section 497/509 that a General Meeting of Members of the above named company will be held at Ward No. 8. Gandhi Nagar, Hamirpur on the 20th day of June, 2002 at 10.40 '0' Clock for the purpose having an account laid before them showing the manner in which the winding up has been conducted and the property of the company disposed off and of hearing any explanation that may be given by the Liqudiator and also of determining by a Special Resolution of the company, the manner in which the books of accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed off.

Dated 22nd day of May, 2002.

For H. M. G. F. HIRE PURCHASE PVT. LIMITED IN LIQUIDATION

Sd/-
(KASAMIR SINGH THAKUR,
s/o SHRI SHIV DYAL),
Vol Liquidator, Ward No. 8, Ghandi Nagar, Hamirpur, Himachal Pradesh.

In the Court of Dr. J. N. Barowalia, District Judge Kangra at Dharamshala

Civil Appeal No. 9/D/XIII/02
Next date of hearning : 17-6-2002

Ramesh Chand, Sudershan Kumar both sons of Minku, residents of Mohal Bhota, Mauza Tangroti, Tehsil Dharamshala, District Kangra . . *Appellants/Plaintiffs.*

Vs.

1. Desh Raj son of Hari Ram, resident of Mohal Bhota, Mauza Tangroti, Tehsil Dharamshala, District Kangra . . *Respondents/defendants.*
2. General public

Appeal under section 96 of CPC against the Judgement and decree date 12-12-2001 passed by Sub-Judge (I) Dharamshala *vide* which the court below has rejected the suit of the plaintiff now appellant.

To

The general public.

Whereas above noted appeal it has been proved to the satisfaction of this court that respondent No. 2 General Public can not be served through and ordinary way of service. Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, CPC is issued against General Public to appear in this court on 17-6-2002 at 10 A.M. personally through, authorised agent or pleader to defend the appeal failing which *ex parte* proceedings shall be taken against them according to law.

Given under my hand and seal of the court this 30th day of April, 2002.

Seal.

J. N. BAROWALIA,
District Judge,
Kangra at Dharamshala.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जसवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री तरसेम लाल पुत्र गुलजारी लाल, वासी महाल बढ़ाल, तहसील जसवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तरसेम लाल पुत्र गुलजारी लाल, वासी महाल बढ़ाल, तहसील जसवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र चैंचल कुमार कौंडल का जन्म दिनांक 16-8-1995 को गांव बढ़ाल, ग्राम पंचायत बढ़ाल में हुआ परन्तु बिलम्ब होने के कारण ग्राम पंचायत अधिकारी सक्षम अदालत से आदेश मांग रहे हैं। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में नियमानुसार दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः ग्राम जनता व रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 19-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं । अन्यथा जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे । उजर कोई काबिले समायत न होगा ।

आज दिनांक 7-3-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जसवां कोटला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री मिलखी राम सुपुत्र श्री नन्दू आदि, निवासी सकोट, तहसील व जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बाबत रजिस्टर्ड करवाने वसीयतनामा जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम ।

मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान बाला में हर खास व आम को बजरिया मुश्त्री मुनादी करके सूचित किया जाता है कि श्री मिलखी राम सुपुत्र श्री नन्दू आदि, निवासी मुहाल सकोट, तहसील व जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में दरख्वास्त दी है कि श्री रतन चन्द सुपुत्र श्री हरिया, निवासी सकोट हाल निवासी खोली, तहसील व जिला कांगड़ा ने एक वसीयतनामा वहक प्रार्थीगण के नाम लिखवाया है कि उसकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति उसके मरणों उपरान्त प्रार्थीगण के नाम की जावे । जिसकी पेशी तारीख 17-6-2002 इस कार्यालय/अदालत में निश्चित की गई है ।

यदि इस सम्बन्ध में किसी को किसी किस्म का उजर या एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत 10.00 बजे आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । इसके बाद कोई उजर व एतराज काबले समायत न होगा अन्यथा गैर-हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जावेगी ।

आज दिनांक . . . . को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सब-रजिस्ट्रार एवं तहसीलदार,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ।

ब अदालत तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल : दरुस्ती तारीख पेशी : 18-6-2002.

श्री बूटा राम पुत्र श्री रावण, निवासी रहेलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

श्री हीरू राम पुत्र श्री तारा, निवासी रहेलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती इन्द्राज व खाता काश्त बाबत भूमि खाता नं 233, खतौनी नं० 379, खसरा नं० 98, रकबा तादादी 0-00-65 हैक्टेयर, वाक्य मुहाल व मौजा रहेलू ।

प्रार्थी श्री बूटा राम ने उपरोक्त रकबा का प्रार्थना-पत्र दरुस्ती अदालत हजा में प्रस्तुत किया है । प्रतिवादीगण को इस अदालत द्वारा हाजर होने बारा कई बार समन व इश्तहार मुश्त्री मुनादी भेजे गये हैं परन्तु उन पर तामील नहीं हो पा रही है । प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि तिथि 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 13-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत जनाब वी0 आर0 कपिल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री पपिन्दर सिंह पुत्र उजागर सिंह, निवासी संदू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पपिन्दर सिंह पुत्र उजागर सिंह, निवासी संदू, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अचित पठानिया का जन्म तिथि 27-11-1997, को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनोल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री पपिन्दर सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

आज दिनांक 13-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । वी0 आर0 कपिल,
तहसीलदार एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री बी0 आर0 कपिल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री हरबंश लाल पुत्र बेली राम, निवासी नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरबंश लाल पुत्र बेली राम, निवासी कथोड़िया, तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश की है कि उसका भाई किशोरी लाल पुत्र बेली राम, निवासी नौशहरा की मृत्यु तिथि 16-6-1991 को हुई है, जिसकी मृत्यु तिथि पंचायत बसनूर, तहसील शाहपुर में दर्ज न हुई है ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह तिथि 17-6-2002 को या इससे पूर्व हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है । अन्यथा पंचायत को सम्बन्धित उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

मोहर । वी0 आर0 कपिल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री वी0 आर0 कपिल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा

श्री तिलक राज पुत्र डीडो राम, निवासी रिड़कयार, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तिलक राज पुत्र डीडो राम, निवासी नौशहरा, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री अरूणा देवी पुत्री तिलक राज का जन्म तिथि 13-4-1996 को हुआ है । जिसका नाम ग्राम पंचायत रिकड़धार, रिड़कयार शाहपुर में दर्ज नहीं हुआ है ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह तिथि 17-6-2002 को या इससे पूर्व हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है । अन्यथा पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

मोहर । वी0 आर0 कपिल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर जिला कांगड़ा

श्री पून्नू राम पुत्र डैन्फा, निवासी रिड़कयार (द्रौणी), तहसील शाहपुर ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पून्नू राम पुत्र डैन्फा, निवासी रिड़कयार, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री मधू देवी पुत्री प्रशोतम चन्द का जन्म तिथि 25-3-1997 को हुआ है । जिसका नाम ग्राम पंचायत रछयालू, तहसील शाहपुर में दर्ज नहीं है ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम व तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह इस तिथि 17-6-2002 को या इससे पूर्व हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है । अन्यथा पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जाएंगे ।

मोहर । बी0 आर0 कपिल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री बी0 आर0 कपिल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा

श्री लेख राम पुत्र श्री नौधा राम, निवासी किमोड़ियां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लेख राम पुत्र श्री नौधा राम, निवासी कियोड़ियां, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री मनीषा देवी पुत्री श्री लेख राम का जन्म तिथि 7-10-1996 को हुआ है जिसका नाम ग्राम पंचायत रछयाल, तहसील शाहपुर में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम व तिथि ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह तिथि 17-6-2002 को या इससे पूर्व हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा पंचायत सचिव को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

मोहर। बी0 आर0 कपिल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री सोहन लाल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या: 2/2002/एस0 टी0 टी0 तिथि संस्थापना : 4-4-2002
प्रकृति : भू-विभाजन तिथि : 18-6-2002

श्री पंजाबा पुत्र ठुणिया पुत्र साधु, निवासी गांव घुड़ डाकघर व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ... प्रार्थी।

बनाम

1. जन्म सिंह, 2. सुरेश चन्द, 3. सुदर्शन कुमार, 4. राज कुमार, 5. अनिल कुमार, सभी पुत्र प्रमोद सिंह पुत्र बंसी, निवासी याद घुड़, डाकघर व उप-तहसील थुरल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ... प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये भू-विभाजन खाता नं0 67, खतौनी नं0 103, खसरा नं0 1161, 1229/1196 किस्सा 2 कुल रकबा 0-01-06 है0, स्थित मुहाल मन्धाणी, मौजा व उप तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जमाबन्दी 1996-97 के अनुसार।

ऐसी अवस्था में, जबकि न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण में से कुछ को साधारण ढंग से तामील नहीं हो सकती है अतः एतद के माध्यम से उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगणों (जिनमें से कुछ अनुपस्थित चले आ रहे हैं) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18-6-2002 को वर्णित भू0-विभाजन प्रकरण की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पैरवी करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित दिनांक 18-6-2002 को न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध "एक पक्षीय" कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-4-2002 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रिका सहित जारी हुआ।

मोहर। सोहन लाल शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Sub-Judge 1st Class, Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh

Dalip Singh s/o Shri Thakur Singh, r/o Village Banon, Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H. P.) ... *Plaintiff.*

Versus

1. Kuldeep Chand s/o Shri Gorkhu, 2. Smt. Urmila Devi w/o Shri Prem Chand, 3. Sanjay Kumar s/o Prem Chand, 4. Ritu d/o Prem Chand, 5. Anjali Devi d/o Prem Chand, 6. Kumari Anita Minor d/o Prem Chand through Natural Guardian her mother Urmila Devi, 7. Smt. Bimla Devi d/o Gorkhu, 8. Sushil Kumar s/o Faquir Chand, 9 Anil Kumar r/o Faquir Chand, 10. Shri Rakesh Kumar s/o Faquir Chand, 11. Harbans Kumar s/o Faquir Chand, 12. Smt. Manjula d/o Faquir Chand, 13. Smt. Bimla Devi w/o Faquir Chand, 14. Smt. Rooma Devi w/o Shri Dharam Singh, 15. Shri Amar Singh s/o Noopa Ram 16. Shri Dharam Chand s/o Tenan Kumar all r/o Village Banon, Tehsil Jogindernagar, District Mandi (H. P.) ... *Defendants.*

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named defendants are evaiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against them to appear in this court on 17-6-2002 at 10 A.M. to defend the case personally or through an authorised agent or pleader failing which *ex parte* proceedings will be taken against them.

Given under my hand and the seal of the Court this 17th day of May, 2002.

Seal. Sd/-
Sub-Judge 1st Class
Jogindernagar, District Mandi.

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री शौंक राम पुत्र तोतू राम

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र अेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री शौंक राम ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी पोती कुमारी प्रतिभा पुत्री कुंज बिहारी का नाम व जन्म तिथि 7-5-1997 उनकी ग्राम पंचायत घरयाणा के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है। नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत घरयाणा के अभिलेख में दरुस्त किया जाये।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री उक्त आवेदक की पोती का नाम व जन्म उनकी ग्राम पंचायत घरयाणा के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 13-6-2002 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-5-2002 को मेरे इस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
शिमला (ग्रा0), जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिमला (ग्रा0), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

ईश्वर दास पुत्र स्व0 श्री सुख राम ग्राम भरयाल, डा0 बड़ेहरी तहसील व जिला शिमला।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र अेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री ईश्वर दास ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सीमा देवी पुत्री देवी सरन के साथ दिनांक 14-10-1995 को उनकी ग्राम पंचायत टटू (मजठाई,) के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है। नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टटू (मजठाई) में दर्ज करने के आदेश दिये जायें ।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की शादी उनकी ग्राम पंचायत टटू (मजठाई) के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्तिनामा दिनांक 16-6-2002 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत सम्बन्धित को नाम व जन्म तिथि/शादी इनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 15-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
शिमला (ग्रा0), जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

उनवान मकद्दमा :

सुमेर चन्द

बनाम

श्रीमती राधा देवी

जेर धारा 37 हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम दावा सेहत इन्द्राज ।

हरगाह मुकद्दमा बाला में फरीकसानी श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व0 रामकिशन निवासी ग्राम व पत्रालय सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस अदालत से दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 को नोटिस जारी किया गया था क्षेत्रीय कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राधा देवी उपरोक्त वर्णित पता (स्थान) पर रहती नहीं पाई गई तथा इसकी मृत्यु हो चुकी है ।

अतः इश्तहार हजा फरीकसानी श्रीमती राधा देवी या उसके जायज वारसान को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 11 जून 2002 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अमालतन या वकालतन हाजिर आवें । वसूरत दीगर कार्यवाही यक तरफा अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 30-4-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी पांवटा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के प्रवीन, सूरज का जन्म दिनांक 2-5-1995, 15-1-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां नगरपालिका परिषद् पांवटा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में अमालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री मनीष पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 17-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत जारी द्वारा किया गया ।

मोहर । संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री संजय शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री चत्तर सिंह पुत्र श्री राम सरन, निवासी अजैवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चत्तर सिंह पुत्र श्री राम सरन, निवासी अजैवाला, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की नाम वेबी का जन्म दिनांक 15-5-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत घुण्डियों के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में अमालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री चत्तर सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 17-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । संजय शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्रीमती विमला देवी, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 45/2002 ता0 मरजुआ : 14-5-2002.

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री तोता राम, निवासी संगड़ाह (डाहर) तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये दरुस्ती कागजात माल ।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में एक दरख्वास्त इस आशय के साथ गुजारी है कि उसकी जाति कागजात माल वर्ष 1953-1954

में भाट (ब्राह्मण भारद्वाज) दर्ज है परन्तु हाल के रिकार्ड में उसकी जाति ब्राह्मण भारद्वाज दर्ज है जो कि गलत है जिसकी वह दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी शख्स को प्रार्थी उपरोक्त की जाति कागजात माल में भाट (ब्राह्मण भारद्वाज) दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबले समायत न होगी तथा प्रार्थी के पक्ष में आवश्यक इन्द्राज कागजात माल में कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 13-5-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। विमला देवी,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

In the court of Shri J. C. Sharma, Assistant Collector, 1st Grade, Kasauli, Distt. Solan (H. P.)

Case No.	Nature of case	Date of Instt.	Date of Dec.
12/13-A of 2002.	Suit for declaration.	10-5-2002	—

Name of Village	Pargana	Tehsil	District
Dhar ke-ber	Lachrang	Kasauli	Solan

Sh. Gurbachan Singh s/o late Shri Gopal Singh s/o Sh. Sunder Singh Shop-Keepar, Subathu Road Bazar, Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H. P.)

..*Plaintiff.*

Versus

1. The general public
2. The Naib Tehsildar (Sales) *cum*-Managing Director, H. P. Shimla

..*Defendants.*

Suit for declaration under section 37 & 46 of the H. P. Land Revenue Act to the effect that the Shop No. 12 Dharampur standing in the name of Smt. Ishar Kaur wd/o late Sh. Harnam Singh Subathu Road, Dharampur, Tehsil Kasauli is situated in Abadi Deh Area Khasra No. 92 Min, Village Dhar-ke-ber, Pargana Lachrang, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H. P.) is situated there. Members of the public and repondents are invited to file any objection if so desired in the court of undersigned at 10 A. M. on 17-6-2002.

Whereas the plaintiff has moved an application before this court praying therein that the shop No. 12 was transferred by the Naib Tehsildar (Sales) *cum*-Managing Director Una, Distt. Kangra (H. P.) has sold the above said shop in the name Smt. Ishar Kaur wd/o Sh. Harnam Singh resident of village Dharampur, Tehsil Kasauli through a sale deed No. 25 dated 6-4-1970 which was registered in the office of the Sub Registrar, Kasauli. Now the plaintiff has further prayed that the name of village Dhar-ke-ber, Pargana Lachrang, Tehsil Kasauli may be replaced for (Dharampur) Pargana Lachrang, Tehsil Kasauli as indicated in the aforesaid conveyancing deed. Hence this proclamation is made for the general public/defendants that they have any objection the same may be produced in this court on 17-6-2002 at 10.00 A. M. Thereafter no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of May, 2002.

Seal. J. C. SHARMA,
Assistant Collector 1st Grade,
Kasauli, Distt. Solan (H. P.).

In the Court of Shri J. C. Sharma, Assistant Collector, 1st Grade Kasauli, Distt. Solan (H. P.)

Case No	Nature of case	Date of Instt.	Date of Dec.
11/13-A of 2002.	Suit for declaration	10-5-2002	—

Name of Village	Pargana	Tehsil	District
Dhar-ke-ber	Lachrang	Kasauli	Solan

Smt. Balwant Kaur widow of late Sh. S. Gopal Singh son of late S. Sunder Singh resident of village Dharampur, Tehsil Kasauli, Distt. Solan (H. P.)

..*Plaintiff.*

Versus

1. General Public through Publication./Proclamation.
2. The Naib Tehsildar (Sales) *cum*-Managing Director, Shimla

..*Defendants.*

Suit for declaration under section 37 &46 of the H. P. Land Revenue Act to the effect that the shop No. 10 Dharampur (Subathu Road), Tehsil Kasauli is situated in the Abadi Deh area, Khasra No. 92 Min, Village Dhar-ki-Ber, Pargana Lachhrang, Tehsil Kasauli, Distt Solan, H. P. Said Shop stands in the name of deceased husband of the Plaintiff, late Shri Gopal Singh. Members of the public & respondents are invited to raise any objection, if so desire, by attending this Court at 10.00 A. M. on 17-6-2002.

Whereas the plaintiff has moved an application before this court praying therein that the shop No. 10 was transferred by the Naib Tehaildar (Sales) *cum*-Managing Directors, Una Distt. Kangra (H. P.) has sold the above said shop in the name of Shti Gopal Singh s/o Sh. Sunder Singh resident of Village Dharampur, Tehsil Kasauli through a sale deed No. 59, dated 18-12-1972 which was registered in the office of Sub Registrar, Kasauli. Now the plaintiff has further prayed that the name of Village Dhar-ke-ber, Pargana Lachrang, Tehsil Kasauli may be replaced for (Dharampur) as indicated in the aforesaid conveyancing deed. Hence this proclamation is made for the general public/defendants that they have any objection the same may be produced in this court on 17-6-2002 at 10-00 A. M. Thereafter no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal of the court on this 10th day of May, 2002.

Seal. J. C. SHARMA,
Assistant Collector 1st Grade.
Kasauli, Distt. Solan (H. P.)

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना०), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री पंजू राम पुत्र श्री मकोड़ू राम, निवासी गवालसर, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पंजू राम पुत्र श्री मकोड़ू राम, निवासी गांव गवालसर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम मनोज कुमार पुत्र श्री पंजू राम का जन्म दिनांक 11-10-2001

को हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री पंजू राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री केवल सिंह, निवासी गांव पंजोड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री केवल सिंह निवासी गांव पंजोड़ा तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र अमन चौधरी की माता-पिता का नाम नत्था व सत्या देवी पंचायत रिकार्ड कुठियाड़ी में गलत लिखा गया है जो कि वीना व केवल सिंह दर्ज होना चाहिए। अतः पंचायत रिकार्ड कुठियाड़ी में उसके पिता व माता का नाम नत्था व सत्या देवी की जगह वीना माता व केवल सिंह पिता दर्ज किया जावे।

अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी नैहरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी गांव नैहरी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम प्रशांत हवलदार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह का जन्म दिनांक 30-1-2002 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नैहरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री वीरेन्द्र सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री राम सरन, निवासी जोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री राम सरन, निवासी जोह, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसने अपनी बेटी यमुना देवी का नाम बदलकर अंकिता रानी रख लिया है। अतः पंचायत रिकार्ड में उसकी बेटी का नाम यमुना देवी की जगह अंकिता रानी दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रितु रानी पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव धर्मशाला महन्ता, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती रितु रानी पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव धर्मशाला महन्ता, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका व उसके बेटे का नाम पंचायत रिकार्ड में गलत दर्ज है। पंचायत रिकार्ड में उसका नाम रितु रानी की जगह प्रवीण कुमारी दर्ज है और बेटे का नाम प्रादर्श हवलदार की जगह अवतार सिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम

रितु रानी व उसके बेटे का नाम आदर्श बडवाल दर्ज होना चाहिए जो सही है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जाएंगें ।

आज दिनांक 15-5-2002 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री कौशल सुनील पुत्र श्री दिलबाग सिंह, निवासी गांव मवा कहोला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री कौशल सुनील पुत्र श्री दिलबाग, निवासी गांव मवा कहोला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में पिंकू दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम पिंकू की जगह कौशल सुनील दर्ज होना चाहिए जो सही है । अतः उसका नाम राजस्व रिकार्ड में पिंकू की जगह कौशल सुनील दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री कौशल मनील पुत्र श्री दिलबाग सिंह, निवासी मवा कहोला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री कौशल मनील पुत्र श्री दिलबाग सिंह, निवासी मवा कहोला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में रिकू दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम रिकू की बजाय कौशल मनील है जो सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रिकू की जगह कौशल मनील दर्ज किया जाए ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिये जाएंगे ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी कुठ्ठा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी गांव कुठ्ठा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम सेजल पुत्री श्री पवन कुमार का जन्म दिनांक 28-9-2001 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड रिपोह मिसरा में दर्ज नहीं करा सकी है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती ऊषा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री गुलाब प्रशाद, निवासी दियोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री गुलाब प्रशाद, निवासी गांव दियोली ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम प्रिया देवी पुत्री श्री प्रकाश कुमार का जन्म दिनांक 23-1-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दियोली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री प्रकाश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ऊषा कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी कुठेड़ा जसवालां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ऊषा कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव कुठेड़ा जसवालां ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम पंकज कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार का जन्म दिनांक 28-2-1995 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुठेड़ा जसवालां के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती ऊषा कुमारी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अवतार सिंह, निवासी मवां कहोलां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर-धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अनीता रानी पत्नी श्री अवतार सिंह, निवासी गांव मवां कहोला ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम कोमल पुत्री श्री अवतार सिंह का जन्म दिनांक 31-1-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसको जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड मवां कहोलां में दर्ज नहीं करा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती अनीता रानी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सतपाल पुत्र श्री वचन सिंह, निवासी अमलैहड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

ग्राम जनता

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्री सतपाल पुत्र श्री वचन सिंह, निवासी अमलैहड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसने अपने बेटे रोहित जसवाल का नाम बदल कर अंकित जसवाल रख लिया है। अतः पंचायत रिकार्ड में उसका नाम रोहित जसवाल की जगह अंकित जसवाल दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री दौलत राम सुपुत्र श्री हुकमी राम, निवासी गोन्दपुर बनेहड़ा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर-धारा 13(3)जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दौलत राम सुपुत्र श्री हुकमी राम, निवासी गांव गोन्दपुर बनेहड़ा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता का नाम जमुना देवी पत्नी श्री हुकमी राम की मृत्यु दिनांक 03-12-2001 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गोन्दपुर बनेहड़ा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री दौलत राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर। नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री अवतार सिंह सुपुत्र श्री विधि चन्द, निवासी पतेहड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अवतार सिंह सुपुत्र श्री विधि चन्द, निवासी गांव पतेहड़ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बच्चों का नाम आशीश व कुमारी अनीता पुत्र/पुत्री श्री अवतार सिंह का जन्म दिनांक 07-09-1999 व 16-5-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नैहरी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री अवतार सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत मे जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री तिलक राज सुपुत्र श्री मल्लु, निवासी चलेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तिलक राज सुपुत्र श्री मल्लु, निवासी गांव चलेट ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम दिपोका सुपुत्री श्री तिलक राज का जन्म दिनांक 11-10-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चलेट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री तिलक राज पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0)
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गुरमीत कौर विधवा स्व0 श्री गुरदेव सिंह, निवासी अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गुरमीत कौर विधवा स्व0 श्री गुरदेव सिंह, निवासी गांव अम्बोटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति का नाम गुरदेव सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह की मृत्यु दिनांक 14-4-1990 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अम्बोटा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती गुरमीत कौर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी कुठेड़ा जसवालां, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी गांव कुठेड़ा जसवालां ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम नवीन शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार का जन्म दिनांक 16-07-1998 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुठेड़ा जसवालां के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री अशोक कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री शीतल दास पुत्र श्री राम लोक, निवासी भंजाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शीतल दास पुत्र श्री राम लोक, निवासी गांव भंजाल ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का नाम सीमा देवी पुत्री श्री शीतल दास का जन्म दिनांक 19-10-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड अप्पर भंजाल में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना पत्र श्री शीतल दास पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी त्रिभवन चन्द्र, निवासी अमोकलां सिद्ध, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री त्रिभवन चन्द्र, निवासी अमोकलां, सिद्ध, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके बेटे का नाम पंचायत रिकार्ड में अरुण भारद्वाज दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम माधवेन्द्र भारद्वाज है जो कि सही है। अतः उसका नाम पंचायत रिकार्ड में अरुण भारद्वाज की जगह माधवेन्द्र भारद्वाज दर्ज किया जाए जो सही है ।

अतः सर्वसाधारण इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 15-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री के0 एस0 चौधरी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बंगाणा, जिला ऊना

श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री जैण्ड, जात चमार, गांव बुढवार, तप्पा टिहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ... प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता गांव बुढवार, तप्पा टिहरा ... प्रतिवादीगण ।

प्रार्थना-पत्र बरामे नाम प्रवीण कुमारी के बजाये रजनी देवी दर्ज करने हेतु ।

इश्तहार मुनादी बनाम ग्राम जनता ।

श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री जैण्ड ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी लड़की का सही नाम रजनी देवी है परन्तु ग्राम पंचायत बुढवार के अभिलेख में प्रवीण कुमारी गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती हेतु प्रार्थना की है ।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनाक 17-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री उत्तम चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 19-4-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । के0 एस0 चौधरी,
सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग बंगाणा,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री के0 एस0 चौधरी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना

मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण पत्र पेशी : 17-6-2002.

जसविन्दर कौर पत्नी सतपाल, गांव घड़ो, तप्पा मुच्छाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना । ... प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता तप्पा मुच्छाली, तहसील बंगाणा ... प्रतिवादीगण ।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता ।

श्रीमती जसविन्दर कौर पत्नी सतपाल पुत्र अमर नाथ, गांव घड़ो, तप्पा मुच्छाली, तहसील बंगाणा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि इस के पुत्र नरिन्द्र सोनी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है अब दर्ज करवाया जाये । इसके पुत्र नरिन्द्र सोनी की जन्म तिथि 16-9-1992 है तथा बच्चे का जन्म स्थान गांव घड़ो है ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज होने में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन होने के पश्चात एक माह के अन्दर-अन्दर असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर होकर पेश करें अन्यथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश सम्बन्धित कार्यालय को दे दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 19-4-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । के0 एस0 चौधरी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ।

सुरेन्द्रपाल सिंह रायजादा बनाम आम जनता लाल सिंगी ।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह रायजादा पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी गांव लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र अशवनी रायजादा का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जाए । इसके पुत्र की जन्म तिथि 19-8-1971 है तथा बच्चे का जन्म गांव लाल सिंगी में हुआ है ।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवाने बारे कोई उजर/आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-6-2002 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 16-5-2002 मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री डी0 आर0 हीरा, तहसीलदार चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा.—जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रमाण-पत्र :

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

निम्नलिखित व्यक्तियों ने इस कार्यालय में इस आशय के साथ निवेदन किया है कि उनका इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है ।

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पिता/पति/पुत्री/पुत्र का नाम	जन्म तिथि	गांव	पंचायत
1	2	3	4	5	6
1.	कमला शर्मा	पत्नी जय राम	28-12-1989	वहेवडी	वहेवडी/देवत
2.	शमीम बेगम	लतीफ खान	5-5-1997	शंठा	देवत
3.	नूर अहमद	आलमगीर	50 वर्ष	पपास	मशडोह
4.	गुलाबू	नूर अहमद	35 वर्ष	,,	,,
5.	बानो	गुलाबू	32 वर्ष	,,	,,
6.	आयशा	आलमगीर	21 वर्ष	,,	,,
7.	जुलेखो	नूर मोहम्मद	12 वर्ष	,,	,,
8.	जैनब	गुलाबू	2 वर्ष	,,	,,
9.	जैतन	,,	1 वर्ष	,,	,,
10.	चरू	सुरेन्द्र	8-6-1997	जरेत	चानू
11.	कु0 डिम्पल	भोपिन्द्र सिंह	5-10-1997	चीला	,,
12.	रोशन लाल	शोभ राम	15-4-1972	अहनोग	चेता
13.	रमा देवी	पत्नी रोशन लाल	18-8-1977	,,	,,
14.	प्रियंका	शिव राम	19-3-1998	सिहाडा	पुन्छ
15.	पियूश	पुत्री प्रेम प्रकाश	10-4-1999	खगना	खगना
16.	अनीता	पुत्री कृष्ना देवी	31-12-1991	टन्डाई	चैता
17.	कृष्ना देवी	भगत राम	20-8-1971	,,	,,
18.	प्रकाश चन्द	शेर सिंह	12-1-1998	मनाह	,,
19.	सत्या कुमारी	,,	12-8-1997	,,	,,
20.	बबीता देवी	मदन सिंह	12-1-1978	झीना	झीना
21.	अकीत	,,	2-1-2001	,,	,,
22.	गणेश कुमार	जोवा लाल	1-1-1969	डकोली	फेडिमा
23.	अनीता	प्रकाश	12-12-1996	गयालड	जखोली
24.	कु0 सरेखा	प्रेम सिंह	15-3-1997	भूठ	,,
25.	तालुब हुसैन	दिल मोहम्मद	37 वर्ष	पवास	मशडोह
26.	ताजू	,,	26 वर्ष	,,	,,
27.	सीटू	,,	15 वर्ष	,,	,,
28.	माम सैन	,,	12 वर्ष	,,	,,
29.	अब्बदुल गनी	पुत्र दिल मोहम्मद	33 वर्ष	,,	,,
30.	बानु	पत्नी ,, ,,	25 वर्ष	,,	,,
31.	रेशमा	पुत्री ,, ,,	15 वर्ष	,,	,,
32.	मुहम्मद हसन	पुत्र ,, ,,	13 वर्ष	,,	,,
33.	शौफत	,, ,, ,,	8 वर्ष	,,	,,
34.	आलिया	,, ,, ,,	35 वर्ष	,,	,,
35.	नूर	पत्नी आलिया	32 वर्ष	,,	,,
36.	फरमू	पुत्र ,, ,,	18 वर्ष	,,	,,
37.	हनीफ	,, ,, ,,	16 वर्ष	,,	,,

1	2	3	4	5	6
38.	तालब मैन	पुत्र आलमगीर	42 वर्ष	,,	,,
39.	बानो	पत्नी ,, ,,	40 वर्ष	,,	,,
40.	हुसन	पुत्री ,, ,,	21 वर्ष	,,	,,
41.	साकीना	,, ,, ,,	15 वर्ष	,,	,,
42.	गुलाम	,, ,, ,,	12 वर्ष	,,	,,
43.	जूर हुसैन	पुत्र आलमगीर	45 वर्ष	,,	,,
44.	नेक बीबी	पत्नी जुर हुसैन	40 वर्ष	,,	,,
45.	शमशेर	पुत्र ,, ,,	35 वर्ष	,,	,,
46.	रोशनी	पुत्री ,, ,,	30 वर्ष	,,	,,
47.	नजीर	पुत्र शमशेर	3 वर्ष	,,	,,
48.	नूर आलम	पुत्र आलमगीर	38 वर्ष	,,	,,
49.	फतीजा	पुत्री नूर आलम	36 वर्ष	,,	,,
50.	जैनत	,, ,, ,,	16 वर्ष	,,	,,
51.	ऐनम	,, ,, ,,	14 वर्ष	,,	,,
52.	मलका	,, ,, ,,	11 वर्ष	,,	,,

सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इनकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत मिति 17-6-2002 को आवे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-5-2002 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

डी० आर० हीरा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला, (हि० प्र०)।

In the Court of Shri Kirpa Ram Sharma, Executive Magistrate, Nerwa

Shri Dhiraj Kapil s/o Shri Manohar Kapil r/o Village Nerwa. Pargna Chandlog. Sub-Tehsil Nerwa (H. P.).

Vs.

General Public

Application u/s 13 (3) death and birth Registration Act, 1969.

ORDER

Shri Dhiraj Kapil s/o Manohar Kapil r/o Village Nerwa. Pargna Chandlog. Sub-Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H. P.) has applied u/s 13 (3) death and birth Registration Act, 1969 for seeking order to Secretary G. P. Nerwa for making entry of name and date of birth his sons Mr. Krtive & Abril who were born on 9-4-2000 and 28-9-2001.

Whereas the General Public has been made as repondent and the undersigned is satisfy that the General Public can not be summoned ordinarily and have this proclamation u/o 5 rule 20 CPC is issued and General Public is called/summoned hereby in order to file the objections if any on or before 12-6-2002 at 10 A. M. before the undersigned. Failing which an *ex party* order shall be passed and the case would be disposed of accordingly.

Given under my hand and seal of the court today on 24-5-2002.

Seal.

KIRPA RAM SHARMA,
Executive Magistrate,
Nerwa, Distt. Shimla (H. P.).

In the Court of Shri Kirpa Ram Sharma, Executive Magistrate Nerwa

Shri Ashwani s/o Shri Payara Lal r/o Village Nerwa, Distt. Shimla (H. P.).

Vs.

General Public

Application u/s 13 (3) death and birth Registration Act, 1969.

ORDER

Shri Ashwani Kumar s/o Payara Lal r/o Village Nerwa, Pargna Chandlog. Sub-Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H. P.) has applied u/s 13 (3) death and birth registration Act, 1969 for seeking order to Secretary G. P. Nerwa for making entry of name and date of birth his daughter Kumari Ishika. who born on 19-12-2000.

Whereas the General Public has been made as respondent and the undersigned is satisfy that the General Public can not be summoned ordinarily and have this proclamation u/o 5 rule 20 CPC is issued and General Public is called/summoned hereby in order to file the objections if any on or before 12-6-2002 at 10 A. M. before the undersigned failing which an *ex-parte* order shall be passed and the case would be disposed of accordingly.

Given under my hand and seal of the court today on 24-5-2002.

Seal.

KIRPA RAM SHARMA,
Executive Magistrate, Nerwa,
Distt. Shimla (H. P.).

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

-शून्य-

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

-शून्य-

अनुपूरक

-शून्य-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित